

**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**उद्घोषित किया गया: 23 मई 2023**

सि.वा. (वाणि.) 246/2021

आर.डी.बी. और कं. एच.यू.एफ.

द्वारा:

..... वादी  
श्री हेमंत दासवानी, श्री सिद्धांत  
श्रीवास्तव और श्री सरबप्रीत  
सिंह, अधिवक्तागण

बनाम

हार्परकॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

द्वारा:

..... प्रतिवादी  
सुश्री स्वाती सुकुमार, सुश्री  
आशिमा ओभन, सुश्री तारिका  
पिल्लई, श्री नवीन नागार्जुन  
और सुश्री तारिणी सहाय,  
अधिवक्तागण

**कोरम:**

**माननीय न्यायाधीश श्री सी. हरि शंकर**

**निर्णय**

**23.05.2023**

**अंतर.आ. 9516/2021 में सि.वा.(वाणि) 246/2021**

## मुद्दा

1. यदि फ़िल्म के निर्माता द्वारा लेखक को पटकथा लिखने का कार्य सौंपा गया है, तो उस फ़िल्म की पटकथा के प्रतिलिप्यधिकार का मालिक कौन होगा, फ़िल्म का निर्माता, या पटकथा का लेखक?
2. वर्तमान मामले में यही प्रश्न विचारणीय है। विचाराधीन फ़िल्म 'नायक' है, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी और इसे भारत रत्न सत्यजीत रे की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है, जो निर्विवाद रूप से अभिलिखित फ़िल्म इतिहास के महानतम निर्देशकों में से एक थे।

## संक्षेप में विवाद

3. वादी-एच.यू.एफ. के कर्ता कहे जाने वाले आर.डी. बंसल द्वारा सत्यजीत रे को फ़िल्म "नायक" की पटकथा लिखने और निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था। सत्यजीत रे ने पटकथा लिखी और फ़िल्म का निर्देशन भी किया।
4. पहले ही कलात्मक अमरता प्राप्त कर चुके सत्यजीत रे ने 23 अप्रैल 1992 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया।
5. 2018 में या उसके आसपास, श्री भास्कर चट्टोपाध्याय ने "नायक" की पटकथा को उपन्यास का रूप दिया। उपन्यास प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित किया गया था और 5 मई 2018 को रिलीज़ किया गया था।

6. वादी "नायक" की पटकथा के प्रतिलिप्यधिकार का मालिक होने का दावा करता है।

7. इसलिए, वर्तमान वाद में आरोप लगाया गया है कि भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा पटकथा को उपन्यास का रूप देना और प्रतिवादी द्वारा उपन्यास का प्रकाशन, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 51<sup>1</sup> के अर्थ के तहत, वादी के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन है।

---

<sup>1</sup> 51. प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब होगा।—किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हुआ समझा जाएगा—

(क) जब कोई व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों का अथवा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी शर्त का उल्लंघन करके—

(i) कोई ऐसी बात करता है जिसे करने का अनन्य अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रदत्त है, या

(ii) किसी स्थान का उपयोग, उस कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित किए जाने के लिए, जब ऐसे संसूचित किए जाने से उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है. लाभ के लिए अनुज्ञात करता है, उस दशा के सिवाय जिसमें वह यह नहीं जानता था और उसके पास यह विश्वास करने का समुचित आधार नहीं था कि सार्वजनिक रूप से ऐसा संसूचित किया जाना प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होगा, अथवा]

(ख) जब कोई व्यक्ति उस कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां—

(i) विक्रय या भाड़े के लिए बनाता है या विक्रीत करता है या भाड़े पर देता है, या व्यापार के तौर पर संप्रदर्शित करता है या विक्रय या भाड़े के लिए प्रतिस्थापित करता है, या

(ii) व्यापार के प्रयोजन के लिए इतने परिमाण में वितरित करता है जिससे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(iii) व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, या

(iv) भारत में आयात करता है

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी, "नायक" की पटकथा पर वादी के प्रतिलिप्यधिकार के दावे पर विवाद करता है। प्रतिवादी के अनुसार, पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार श्री सत्यजीत रे के पास है। 1992 में उसकी मृत्यु के बाद, पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार उसके बेटे संदीप रे और सोसाइटी फ़ॉर प्रिज़र्वेशन ऑफ़ सत्यजीत रे आर्काइव्स (—"एस.पी.एस.आर.ए.", इसके बाद), जिसके संदीप रे सदस्य हैं, के पास चला गया। प्रतिवादी का दावा है कि उसने फ़िल्म की पटकथा को उपन्यास का रूप देने के लिए संदीप रे और एस.पी.एस.आर.ए. से अनुज्ञप्ति प्राप्त की है।
9. इसलिए विचार के लिए मुख्य मुद्दा यह उठता है कि फ़िल्म की पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार सत्यजीत रे के पास है या आर.डी. बंसल के पास है। विधि के प्रश्न के रूप में, आम तौर पर, जो मुद्दा विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या, ऐसे मामले में जहाँ फ़िल्म की पटकथा का लेखक पारिश्रमिक के विरुद्ध निर्माता के साथ एक संविदा के तहत ऐसा करता है, पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार लेखक के पास होगा या निर्माता के पास।

### वर्तमान आवेदन

---

[परंतु उपखंड (iv) की कोई बात, आयातकर्ता के निजी और घरेलू उपयोग के लिए, किसी कृति की एक प्रति के आयात को लागू नहीं होगी।]

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति से चलचित्र फिल्म के रूप में पुनरुत्पादन को "अतिलघनकारी प्रति" समझा जाएगा।

10. यह निर्णय अंतर.आ. 9516/2021 का न्यायनिर्णय देता है, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) के आदेश XIII A नियम 4 के तहत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी, उक्त आवेदन द्वारा, वाद को बिना किसी वादहेतुक के खारिज करते हुए एक सारांश निर्णय चाहता है।

11. हालाँकि, सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति सुकुमार ने वर्तमान आवेदन में अपनी राहत को वादपत्र में प्रार्थना (क) की संक्षिप्त अस्वीकृति तक संक्षेप में दिया है, जो इस प्रकार है :

“34. इन परिस्थितियों में, वादी निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है :

क. प्रतिवादी को स्वयं या उसके डीलरों, वितरकों, थोक व्यापारियों, एजेंटों, सहयोगियों, सहयोगी संस्थाओं, कर्मचारियों, नौकरों और/या नियुक्तियों के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म 'नायक' के संबंध में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्युत्पन्न फिल्म/स्क्रिप्ट के उपन्यासीकरण में शामिल किसी भी कार्य को बनाने, बेचने, बिक्री के लिए पेश करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री, जो वादी के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन है;”

इसलिए, यह निर्णय केवल इस बात की जाँच करता है कि क्या वाद में प्रार्थना (क) को मौखिक साक्ष्य और परीक्षण के अधीन देखा जाना चाहिए, या सुश्री

सुकुमार की माँग के अनुसार सीधे खारिज किया जा सकता है, इस आधार पर कि वादी की प्रार्थना पूरी होने की कोई संभावना नहीं है।

12. मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमन्त दासवानी और प्रतिवादी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति सुकुमार को काफ़ी विस्तार से सुना है।

13. विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ भी अभिलेख पर पेश की गई हैं। वादी की ओर से 16 जुलाई 2021 और 2 मई 2023 को लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की गईं, जबकि प्रतिवादी की ओर से 12 अक्टूबर 2021 और 16 जुलाई 2021 को लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की गईं।

## परस्पर विरोधी मत

अभिवचनों में परस्पर विरोधी मत

## वादपत्र

14. वादपत्र में जोर दिया गया है कि, 1965-66 में, आर.डी. बंसल ("इसके बाद "आर.डी.बी.") ने सत्यजीत रे को फ़िल्म "नायक" की पटकथा लिखने और निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया था। वादी-एच.यू.एफ़. आर.डी.बी. के स्वामित्व में उत्तराधिकारी होने का दावा करता है। "नायक" के निर्माता के रूप में,

वादपत्र का दावा है कि फ़िल्म में प्रतिलिप्यधिकार, साथ ही फ़िल्म से जुड़े सभी अप्रत्यक्ष, व्युत्पन्न और संबंधित अधिकार, हर समय आर.डी.बी. के पास हैं।

15. वादपत्र का पैरा 5(क) इस प्रकार एक पटकथा को एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट से भिन्न करने का प्रयास करता है :

“5(क) इस बिंदु पर यह इंगित करना उचित है कि फ़िल्म की पटकथा लेखक द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट से कहीं अधिक लंबी होती है। पटकथा के भीतर पात्रों की गतिविधियों, क्रियाओं, हाव-भावों और संवादों का भी वर्णन किया जाता है। आम तौर पर इसका मतलब कहानी का विकसित संस्करण है, जो अलग-अलग दृश्यों में विभाजित होता है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण जैसे दृश्य शीर्षक, उस दृश्य की कार्रवाई का विवरण और पात्रों (संवाद) के बीच मौखिक आदान-प्रदान का स्पष्ट संकेत आदि शामिल हैं। यदि दृश्य में वह सब कुछ है जो केवल निर्माता के कहने पर लिखा गया है तभी वह आगे बढ़ता है और उस फ़िल्म के लिए एक विशिष्ट बजट आवंटित करता है जिससे वह सभी व्यावसायिक लाभ या विफलता का जोखिम उठाना चाहता है।”

16. वादी फ़िल्म की पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार का दावा करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17<sup>2</sup> के परंतुकों के खंड (ख) पर निर्भर करता

---

<sup>2</sup> 17. प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कृति का रचयिता उस प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा:

परन्तु –

है। इस संदर्भ में, प्राख्यान दिया गया है कि आर.डी.बी. ने फ़िल्म के निर्माण में सारा पैसा निवेश किया था और इसकी वाणिज्यिक रिलीज़ और वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार था। इसलिए, फ़िल्म की व्यावसायिक विफलता का पूरा जोखिम आर.डी.बी. ने अपने कंधों पर ले लिया। यह प्राख्यान दिया गया है कि आर.डी.बी. फ़िल्म के संबंध में सभी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्युत्पन्न और संबंधित अधिकारों का मालिक बन गया है। वह फ़िल्म का निर्माता और विश्वव्यापी वितरक था और उसने 1966 में फ़िल्म का पहला प्रकाशन किया था। वादपत्र के पैरा 6 से 8 में फ़िल्म के संरक्षण आदि पर आर.डी.बी. द्वारा किए गए खर्चों का विवरण दिया गया है।

- 
- (क) किसी ऐसी साहित्यिक, नाट्य या कलात्मक कृति की दशा में, जो उसके रचयिता द्वारा किसी समाचारपत्र पत्रिका या वैसी ही मामयिकी के स्वत्वधारी द्वारा, सेवा या शिक्षता की संविदा के अधीन उसके नियोजन के अनुक्रम में किस समाचारपत्र, पत्रिका या वैसी ही मामयिकी में प्रकाशन के प्रयोजनार्थ बनाई गई हो, उक्त स्वत्वमारी तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा जहां तक कि प्रतिलिप्यधिकार उस कृति के किसी समाचारपत्र, पत्रिका या वैसी ही सामयिकी में प्रकाशन में अथवा उसके वैसे प्रकाशन के प्रयोजनार्थ उस कृति के पुनरुत्पादना से संबद्ध है, किन्तु अन्य सब बातों के लिए रचयिता कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा,
- (ख) खंड (क) के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि किसी व्यक्ति के अनुरोध पर मूल्यवान प्रतिफल के लिए खींचे गए फोटोग्राफ वा बनाए गए रंगचित्र या चित्र या उत्कीर्ण या चलचित्र फिल्म की दशा में ऐसा व्यक्ति, तत्प्रतिकूल किनी करार के अभाव में, उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा:
- (ग) सेवा या शिक्षता की संविदा के अधीन रचयिता के नियोजन के दौरान बनाई गई किसी कृति की दशा में जिसकी खंड (क) या खंड (ख) लागू नहीं होता नियोजक, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा:
- (घ) किसी सरकारी कृति की दशा में, सरकार, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, उसमें प्रतिलिप्यधिकार की प्रथम स्वामी होगी।
- (ङ) ऐसी कृति की दशा में जिसको धारा 41 के उपबंध लागू होते हैं, संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा।

परंतु किसी चलचित्र कृति में सम्मिलित की गई किसी कृति की दशा में, खंड (ख) और खंड (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात से धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कृति में रचयिता के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;



17. इन परिस्थितियों में, वादी का आरोप है कि 10 अप्रैल 2018 को एस.आर.एस.पी.ए. के एक पत्र द्वारा सूचित किए जाने पर वादी का दुःखी होना न्यायोचित था, कि प्रतिवादी ने फिल्म की पटकथा का औपन्यासिक संस्करण प्रकाशित किया था और जल्द ही पुस्तक लॉन्च करने वाला था। पत्र में उपन्यास के लॉन्च पर फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए वादी की अनुमति माँगी गई थी।

18. इसके बाद, वादी और प्रतिवादी के बीच पत्र की एक शृंखला शुरू हुई, जिसमें वादी ने फिल्म की पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार का दावा किया और प्रतिवादी ने ऐसे सभी दावों का खंडन किया। वादी ने फिल्म की पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार धारक होने का दावा किया, और वादी की जानकारी के बिना और वादी से कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति प्राप्त किए बिना फिल्म के उपन्यासीकरण पर आपत्ति व्यक्त की। इसके विपरीत, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि फिल्म की पटकथा के अधिकार वादी के पास हैं और इसलिए, उसने सत्यजीत रे के विधिक प्रतिनिधियों, अर्थात्, संदीप रे और एस.आर.एस.पी.ए. के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत प्रतिवादी को फिल्म की पटकथा को उपन्यास का रूप देने की अनुमति दी गई थी। वादी ने प्राख्यान दिया गया है कि, 28 मई 2018 को अपने पत्र में, प्रतिवादी ने प्रतिलिप्यधिकार अतिलंघन के तथ्य को स्वीकार किया और उस संबंध में मुआवज़े की पेशकश की।

19. वादपत्र में आगे कहा गया है कि, इसके बाद, प्रतिवादी ने मौखिक रूप से वादी को आश्वासन दिया कि वह फ़िल्म का उपन्यासीकरण करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। उक्त मौखिक आश्वासन के स्पष्ट उल्लंघन में, वादपत्र के पैरा 14 में यह आरोप लगाया गया है कि, 22 अक्टूबर 2020 को, वादी को पता चला कि प्रतिवादी उपन्यास के वैश्विक लॉन्च के लिए आगे बढ़ रहा है। इसके बाद, यह उपन्यास कई ई-कॉमर्स पोर्टलों पर व्यापक रूप से उपलब्ध पाया गया। वादपत्र में आरोप है कि यह फ़िल्म की पटकथा में वादी के प्रतिलिप्यधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

20. फिर, वादी और प्रतिवादी के बीच पत्रों की एक शृंखला चली, जिसमें प्रत्येक ने दूसरे द्वारा दिए गए अधिकारों पर विवाद किया।

21. इन्हीं परिस्थितियों में वादी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान वादपत्र दायर किया था। वादपत्र को बाद में अंतर.आ. 10986/2021 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसे इस न्यायालय ने 8 सितंबर 2021 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी।

22. इसके बाद, प्रतिवादी ने सारांश निर्णय के लिए आदेश XIIIक के तहत आवेदन दायर किया, जिसका यह निर्णय निपटान करता है।

## प्रतिवादी का लिखित बयान

23. प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से, प्रतिवादी लिखित बयान में निम्नानुसार तर्क देता है:

(i) वाद खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि वादी ने पटकथा भी अभिलेख पर पेश नहीं की है, जो प्रतिलिप्यधिकार दावे का आधार है, जिस पर वाद दायर किया गया है। न ही उक्त पटकथा और चुनौती की विषयवस्तु बनाने वाले उपन्यास के बीच कोई तुलना प्रदान की गई है।

(ii) वादपत्र का पैरा 5 सत्यजीत रे को फ़िल्म का लेखक और निर्देशक मानता है। फ़िल्म के लेखक के रूप में, सत्यजीत रे, वास्तव में, इसकी पटकथा और स्क्रिप्ट में प्रतिलिप्यधिकार के मालिक होंगे, क्योंकि वे फ़िल्म से अलग, स्वतंत्र साहित्यिक कृतियों का गठन करते हैं। वादपत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि वादी स्क्रिप्ट और पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार का पहला मालिक है, न ही कोई ऐसा अभिवचन है कि वादी को सत्यजीत रे या उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा स्क्रिप्ट और पटकथा में

प्रतिलिप्यधिकार का अधिकार सौंपा गया था। इस प्रकार, वाद वादहेतुक रहित है।

24. प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया है कि उसने फ़िल्म के ऐसे किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं किया है जिस पर वादी का प्रतिलिप्यधिकार है। प्रतिवादी ने आक्षेपित उपन्यास में केवल फ़िल्म की पटकथा का उपयोग किया है, जो एक साहित्यिक कृति है, साथ ही फ़िल्म की स्थिर तस्वीरों का भी उपयोग किया है, जिसका प्रतिलिप्यधिकार भी सत्यजीत रे के पास है। इसलिए, वादी के किसी भी प्रतिलिप्यधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

25. लिखित बयान सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म और उसके अंतर्निहित कार्यों के बीच अंतर करता है। यह कहा गया है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट, पटकथा और स्थिर तस्वीरें "अंतर्निहित कार्य" का गठन करती हैं। किसी फ़िल्म पर निर्माता का अधिकार फ़िल्म के भौतिक रूप तक ही सीमित है, और यह फ़िल्म की पटकथा और स्क्रिप्ट जैसे अंतर्निहित कार्यों तक विस्तारित नहीं होता है। फ़िल्म के निर्माता के रूप में वादी के पास अंतर्निहित कार्यों पर कोई अलग प्रतिलिप्यधिकार या उपयोग का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में, यह विशेष रूप से कहा गया है, कि "सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य का प्रतिलिप्यधिकार फ़िल्म में शामिल अंतर्निहित कार्यों के स्वामित्व तक विस्तारित नहीं होता है"।

26. प्रतिवादी ने, इस संदर्भ में, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 13(4)<sup>3</sup> का संदर्भ दिया है, जो प्रतिवादी के अनुसार, इस मुद्दे को कवर करती है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि किसी सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म का प्रतिलिप्यधिकार अंतर्निहित कार्यों के प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, भले ही वे फ़िल्म का एक बड़ा हिस्सा हों। प्रतिवादी ने यह तर्क देने के लिए धारा 2(घ)(v)<sup>4</sup> को भी उद्धृत किया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए लेखकत्व केवल सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के संबंध में वादी के पास है, न कि इसके अंतर्निहित कार्यों के संबंध में। इन प्रावधानों से प्रतिपादित, लिखित बयान

<sup>3</sup> 13. कृतियां जिनमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्वशील है -

(1) इस धारा के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए निम्नलिखित वर्गों की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व समस्त भारत में होगा, अर्थात् -

- (क) मौलिक, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियां;
- (ख) चलचित्र फिल्म; और
- (ग) ध्वन्यंकन।

\*\*\*\*\*

(4) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार, किसी ऐसी रीति में पृथक् प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिसकी या जिसके पर्याप्त भाग की बाबत, यथास्थिति, वह फिल्म या वह ध्वन्यंकन बनाया गया हो।

<sup>4</sup> (घ) "रचयिता" से अभिप्रेत है,-

- (i) किसी साहित्यिक या नाट्यकृति के संबंध में उस कृति का रचयिता,
- (ii) किसी संगीतात्मक कृति के संबंध में, संगीतकार,
- (iii) फोटोग्राफ से भिन्न किसी कलात्मक कृति के संबंध में, कलाकार,
- (iv) किसी फोटोग्राफ के संबंध में, फोटोग्राफ खींचने वाला व्यक्ति..
- (v) किसी चलचित्र फिल्म के संबंध में, इसके पूरा होने के समय फिल्म का स्वामी; या ध्वन्यंकन, निर्माता; और
- (vi) किसी ऐसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के संबंध में, जो कम्प्यूटरजनित है. वह व्यक्ति जो उस कृति का सृजन कराता है;

में ज़ोर दिया गया है कि, एक सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में अंतर्निहित कार्यों के संबंध में, ऐसे कार्यों के लेखक लेखक बने रहेंगे और, परिणामस्वरूप, उसके संबंध में प्रतिलिप्यधिकार धारक बने रहेंगे। उक्त लेखकों में से किसी की ओर से वादी के पक्ष में कोई समनुदेशन नहीं किया गया है।

27. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14(1)(क)<sup>5</sup> पर भरोसा करते हुए यह आगे बताया गया है कि सत्यजीत रे ने केवल स्क्रिप्ट और पटकथा लिखने की

---

<sup>5</sup> 14. प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ -

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिलिप्यधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कृति या उसके किसी पर्याप्त भाग के संबंध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार, अर्थात् :-

- (क) कृति साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की दशा में, जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं है,
- (i) कृति को किसी पर्याप्त रूप में पुनरुत्पादित करना, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी संचार माध्यम में उसका भंडारण है;
- (ii) कार्य को प्रकाशित करना;
- (iii) जनता को कृति की ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन में नहीं हैं;
- (iv) कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;
- (v) कृति के संबंध में कोई चलचित्र फिल्म बनाना या ध्वन्यंकन करना;
- (vi) कृति का कोई भाषान्तर तैयार करना;
- (vii) कृति का कोई अनुकूलन करना;
- (viii) कृति के भाषान्तरण या अनुकूलन के संबंध में ऐसे कार्यों में से कोई कार्य करना जो कृति के संबंध में उपखंड (1) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट है;

\*\*\*\*\*

सहमति दी थी जिसके आधार पर फिल्म बनाई गई थी। सत्यजीत रे की यह सहमति, वादी के पक्ष में स्क्रिप्ट/पटकथा में उनके द्वारा रखे गए प्रतिलिप्यधिकार के किसी समनुदेशन के बराबर नहीं थी। ऐसा कोई भी कार्य एक अलग अनुबंध के माध्यम से होना चाहिए था, और ऐसा कोई अनुबंध अस्तित्व में नहीं था। इसके विपरीत, यह बताया गया कि प्रतिवादी ने सत्यजीत रे के विधिक प्रतिनिधि और एस.पी.एस.आर.ए., जो इसके संबंध में अधिकारवान प्रतिलिप्यधिकार मालिक थे, से पटकथा को उपन्यास का रूप देने का अधिकार प्राप्त किया था।

**28.** यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरा वाद इस दोषपूर्ण उपधारणा पर आधारित था कि सिनेमैटोग्राफिक फिल्म में अंतर्निहित कार्यों के सभी अधिकार स्वचालित रूप से फिल्म के निर्माता के पास चले जाते हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि यह उपधारणा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 19<sup>6</sup> के विपरीत है।

---

(ग) चलचित्र फिल्म की दशा में, निम्नलिखित में से किसी कार्य को करने या करने के लिए प्राधिकृत करना, अर्थात:-

- (i) फिल्म की एक प्रति बनाना;
- (ii) फिल्म को, जहां तक दृश्य छवियों से युक्त है, सार्वजनिक रूप से देखा जाना और, जहां तक इसमें ध्वनियां शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से सुनी जानी हैं;
- (iii) ऐसे साउंड ट्रैक का उपयोग करके फिल्म से संबद्ध साउंड ट्रैक के किसी भाग में रिकार्डिंग को मूर्त रूप देते हुए कोई रिकार्ड बनाना;
- (iv) फिल्म को रेडियो-प्रसार द्वारा संप्रेषित करना;

<sup>6</sup> 19. समनुदेशन का ढंग -

(1) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का कोई समनुदेशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक वह लिखित रूप में और समनुदेशिनी द्वारा या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

29. तथ्यों के आधार पर, लिखित बयान में आगे ज़ोर दिया गया है कि प्रतिवादी ने, वास्तव में, संदीप रे को स्वामिस्व (रॉयल्टी) का भुगतान किया था और संदीप रे के साथ-साथ एस.पी.एस.आर.ए. से फ़िल्म की पटकथा और स्थिर तस्वीरों के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी। 8 जुलाई 2015 को संदीप रे, एस.पी.एस.आर.ए. और उपन्यास के लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय के बीच एक विशिष्ट संविदा निष्पादित की गई थी। फ़िल्म के चित्र और पुस्तक के कवर का उपयोग करने के अधिकार एस.पी.एस.आर.ए. द्वारा वादी को अलग से दिए गए थे। विधि के अनुसार इन अधिकारों को प्राप्त करने के बाद ही पटकथा का उपन्यासीकरण किया गया और उपन्यास 5 मई 2018 को रिलीज़ किया गया।

30. इस प्रकार, लिखित बयान में ज़ोर दिया गया है कि, हर समय, सत्यजीत रे साहित्यिक कार्यों और फ़िल्म से जुड़े कलात्मक कार्यों में प्रतिलिप्यधिकार के मालिक बने रहे, जिसमें फ़िल्म की पटकथा और स्थिर तस्वीरें भी शामिल थीं। यह बताया गया है कि 1968 में बंगाली मोशन पिक्चर्स डायरी ने सत्यजीत रे को "नायक" की पटकथा और कहानी दोनों के लेखक के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए, लिखित बयान वादी के इस दावे को स्पष्ट रूप से नकारता है कि, फ़िल्म के निर्माता के रूप में, वादी वास्तव में फ़िल्म के संबंध में सभी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और व्युत्पन्न अधिकारों का हकदार था।



31. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17 के परंतुक के खंड (ख) पर वादी की निर्भरता गलत है और उचित खंड के रूप में जो लागू होगा, वह वास्तव में, खंड (क) होगा। आगे यह भी कहा गया है कि सत्यजीत रे आर.डी.बी. का कर्मचारी नहीं था, लेकिन आर.डी.बी. और सत्यजीत रे के बीच एक स्वतंत्र संविदा थी।

32. लिखित बयान अंततः वादी के इस प्राख्यान से इनकार करता है कि, अपने संचार में, प्रतिवादी ने फ़िल्म की पटकथा में वादी के प्रतिलिप्यधिकार को स्वीकार किया था। बल्कि, प्रतिवादी प्राख्यान देता है कि, उसने हर समय वादी के उक्त दावे का खंडन किया था और वास्तव में, वादी से दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए कहा था। केवल यह तथ्य कि, उपन्यास के लॉन्च के समय फ़िल्म की स्क्रीनिंग से पहले, वादी की अनुमति माँगी गई थी, किसी भी तरह से, फ़िल्म की पटकथा में वादी द्वारा रखे गए किसी भी प्रतिलिप्यधिकार की स्वीकृति नहीं है।

#### न्यायपीठ के समक्ष परस्पर विरोधी मत

33. उपरोक्त के अलावा, विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी मत, जैसा कि वे बार में तर्कों और अभिलेख पर रखे गए लिखित प्रस्तुतियों से उभरे थे, इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं।

वादी के लिए श्री हेमन्त दासवानी की प्रारंभिक/परिचयात्मक प्रस्तुतियाँ

34. श्री दासवानी का कहना है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17 के परंतुक का खंड (ख) वादी को फ़िल्म की पटकथा के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान धारा 13(4) पर अभिभावी है। फ़िल्म के निर्माता के रूप में, वादी फ़िल्म के प्रतिलिप्यधिकार और अन्य सभी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संबंधित अधिकारों का पहला मालिक था। इस संदर्भ में, *रमेश सिप्पी बनाम शान रणजीत उधमसिंह*<sup>7</sup> मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 47 और *इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी बनाम ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स*<sup>8</sup> (इसके बाद "*आई.पी.आर.एस.*") में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 18 पर भरोसा किया गया है।

35. श्री दासवानी ने पक्षकारगण के बीच आदान-प्रदान किए गए निम्नलिखित ईमेल की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है:

ई-मेल दिनांक 11 अप्रैल 2018 दोपहर 3.15 बजे प्रतिवादी से वादी  
को

“प्रेषक: चौधरी, शांतनु

भेजने की तिथि: बुधवार, 11 अप्रैल 2018, दोपहर 3:15 बजे

<sup>7</sup> 2013 (55) पीटीसी 95 (बॉम्बे)

<sup>8</sup> (1977) 2 एससीसी 829

**प्राप्तकर्ता:** आर.डी.बी. ऑर्गनाइज़ेशन <rdb@rdborganization.com>

**कॉपी:** [satyajitraysociety@gmail.com](mailto:satyajitraysociety@gmail.com)

**विषय:** ध्यान दें: श्री दिलीप मित्रा

प्रिय श्री मित्रा,

हमने इसी के लिए सत्यजीत रे सोसाइटी से संपर्क किया और उनके साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए, जिस पर श्री संदीप रे ने रे सोसाइटी की ओर से हस्ताक्षर किए थे।

हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्क्रिप्ट के अधिकार किसी और के पास हैं। हम इससे पहले कई परियोजनाओं पर रे सोसाइटी के साथ जुड़े रहे हैं, जिसमें सत्यजीत रे द्वारा फिल्माई गई कहानियों के अनुवाद, पाथेर पांचाली पर एक पुस्तक, जिसमें इसकी शूटिंग स्क्रिप्ट और अन्य शामिल हैं। इस प्रकार, हमने मान लिया कि अधिकार सोसाइटी के पास ही हैं।

मैं अरूप से इसकी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा।

सादर अभिवादन

शांतनु

ई-मेल दिनांक 11 अप्रैल 2018 शाम 4.31 बजे एस.पी.एस.आर.ए. से प्रतिवादी को

**प्रेषक:** सत्यजीत रे सोसाइटी

[mailto:satyajitraysociety@gmail.com]

**भेजने की तिथि:** बुधवार 11 अप्रैल 2018, शाम 4:31 बजे

**प्राप्तकर्ता:** चौधरी, शांतनु

<Shantanu.Chaudhuri@harpercollinsindia.com>

**विषय:** उत्तर: ध्यान दें: श्री दिलीप मित्रा

प्रिय शांतनु,

यह कहना गलत है कि सोसाइटी ने आपको सत्यजीत रे द्वारा लिखित नायक की स्क्रिप्ट को उपन्यास का रूप देने की अनुमति दी है। सत्यजीत रे के एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते, संदीप रे के पास सत्यजीत बाबू के लेखन का प्रतिलिप्यधिकार है। रे ने जो स्क्रिप्ट्स लिखीं, वे सत्यजीत बाबू की कुछ रचनाएँ हैं। लेकिन निश्चित रूप से निर्माताओं के पास उन फ़िल्मों के अधिकार हैं जो रे ने बनाईं।

सादर अभिवादन

अरूप

\*\*\*\*\*

ई-मेल दिनांक 28 मई 2018 पर दोपहर 2.35 बजे प्रतिवादी से वादी को

प्रेषक: चौधरी, शांतनु

[\[mailto:Shantanu.Chaudhuri@harpercollins-india.com\]](mailto:Shantanu.Chaudhuri@harpercollins-india.com)

भेजने की तिथि: 28 मई 2018 14:35

प्राप्तकर्ता: आर.डी.बी. ऑर्गनाइज़ेशन

कॉपी: 'सत्यजीत रे सोसायटी'; [kamal@rdborganization.com](mailto:kamal@rdborganization.com);  
[varsha@rdborganization.com](mailto:varsha@rdborganization.com); 'अरूप डे'; 'पिनाकी डे'

विषय: उत्तर: [स्पैम] उत्तर: [स्पैम] उत्तर: हार्परकॉलिन्स के साथ  
मीटिंग

प्रिय श्री मित्रा,

हमने पुस्तक पर अपने अधिकार और संविदा से जुड़े लोगों के साथ लंबी चर्चा की है। यह घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण शृंखला रही है जिसने हमें इस स्थिति तक पहुँचाया है।

संविदा के अनुसार स्थिति हार्पर कॉलिन्स के संबंध में स्पष्ट है: तीसरे पक्ष क्षतिपूर्ति खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा पर हस्ताक्षरकर्ता पुष्टि करता है कि किसी तीसरे पक्ष के प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

जहाँ तक मौद्रिक मुआवज़े का प्रश्न है, संविदा के तहत हम भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। विधिक तौर पर, तृतीय-पक्ष प्रतिलिप्यधिकार खंड हमें स्पष्ट रखता है।

जहाँ तक प्रतिलिप्यधिकार का प्रश्न है, अगर रे सोसाइटी और सत्यजीत रे की फिल्मों के उत्तराधिकारी संदीप दा को प्रतिलिप्यधिकार स्थिति के बारे में पता नहीं था, तो निश्चित रूप से हार्पर में हमारे पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। हमने इस पर हस्ताक्षर उसी आधार पर किया है जिस आधार पर हमने सोसायटी के साथ अपनी बाकी पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए हैं - सभी पुस्तकों के लिए संविदा की शर्तें समान हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे रे सोसाइटी के बाहर किसी को पता चले कि प्रतिलिप्यधिकार आपके अलावा किसी और का हो सकता है।

वास्तव में, अरूप डे ने यहाँ तक उल्लेख किया था कि रे सोसायटी बिल देगी और हमें पुस्तक में तस्वीरों के लिए सोसायटी को भुगतान करना था, जो कि सोसायटी से आई थी और अरूप द्वारा भेजे गई थी (हमें यह भी नहीं पता था कि तस्वीरें भी आपकी थीं क्योंकि यह सोसायटी से आई थीं और अरूप ने सोसायटी को भुगतान करने का उल्लेख किया था)।

अगर हमें इसका अंदाज़ा होता, तो आपको शामिल किए बिना हम आगे नहीं बढ़ते। यह केवल संविदा और वित्त-संबंधी विवरण बदलने की बात थी - संदीप-दा के साथ संविदा के बजाय, यह आपके साथ होता।

दुर्भाग्य से, इन परिस्थितियों और उसके कारण प्रचार-प्रसार की पूरी कमी के कारण, पुस्तक बुरी तरह नाकाम हो गई है। हम संदीप-दा को दी गई अग्रिम राशि भी वसूल नहीं कर पाएँगे। इस प्रकार, जहाँ तक इस पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रश्न है, हम गहरे संकट में हैं। एकमात्र भुगतान जो हम कर सकते हैं वह 10,000 रुपये की राशि है जो हमने उन तस्वीरों के लिए अलग रखी है जो रे सोसायटी ने हमें प्रदान की थी और जिसके लिए अरूप हमें बिल देने जा रहा था (यहाँ तक कि इस राशि की पेशकश करने से भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है)। प्रचार और बिक्री न कर पाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे हार्पर में मेरी स्थिति प्रभावित हुई है - और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है।

और यह अत्यंत दुखद है क्योंकि जिसने भी यह पुस्तक पढ़ी है उसने इसकी प्रशंसा की है। शर्मिला टैगोर ने इसे पटकथा का अनुवाद करने का एक सहज प्रयास कहा, लगभग इस तरह जैसे कि पटकथा उपन्यास से विकसित हुई हो, न कि इसके विपरीत। गुलज़ार जी ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक रूप से कहा था कि उपन्यासीकरण कितना अद्भुत है (और इससे उन्हें अपनी एक फ़िल्म को उपन्यास का रूप देने का विचार आया है!)। शूजीत सरकार ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। हमें उपन्यास के अनुवाद के लिए हिंदी और मराठी प्रकाशकों से प्रस्ताव मिले हैं - जिन्हें हमें रोकना पड़ा है। हार्परकॉलिन्स को मूल रूप से हमारी कोई गलती नहीं होने का खामियाज़ा भुगतना पड़ा है। लेकिन अधिकारों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए, हम सभी इस पुस्तक से लाभान्वित हो सकते थे। आपकी

वित्तीय शक्ति को देखते हुए, अगर हमें संविदा की स्थिति के बारे में पता होता, तो मैंने यह भी सुझाव दिया होता कि क्राइटेरियन और/या आप व्यवसाय प्रचार योजना के रूप में क्राइटेरियन कलेक्शन डीवीडी देने के लिए 50% छूट पर पुस्तक की 2000 प्रतियाँ खरीद सकते हैं। मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि हम किस स्थिति में हैं। और आगे चलकर हम कुछ परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

सादर अभिवादन  
शांतनु”

36. श्री दासवानी प्रस्तुत करते हैं कि इन पत्रों में प्रतिवादी द्वारा फ़िल्म की पटकथा में वादी के प्रतिलिप्यधिकार की स्वीकार्यता शामिल है।

37. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2(घ) के साथ सहपठित धारा 17 के अनुसार, श्री दासवानी ने श्री गोकुलम चिट एंड फ़ाइनेंस कंपनी (प्रा.) लि. बनाम जॉनी सागरिगा सिनेमा स्क्वायर<sup>9</sup> में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 3, 21 से 29 पर भरोसा जताया है। श्री दासवानी ने प्रतिवादी द्वारा वादी को दिनांक 28 मई 2018 के भेजे गए ईमेल के निम्नलिखित अंश पर भी ज़ोर दिया:

“और यह अत्यंत दुखद है क्योंकि जिसने भी यह पुस्तक पढ़ी है उसने इसकी प्रशंसा की है। शर्मिला टैगोर ने इसे पटकथा का अनुवाद करने का एक सहज प्रयास कहा, लगभग इस तरह जैसे कि पटकथा उपन्यास से विकसित हुई हो, न कि इसके विपरीत। गुलज़ार जी ने

---

<sup>9</sup> 2011 (3) सीटीसी 747 (मद्रास)



पिछले सप्ताह सार्वजनिक रूप से कहा था कि उपन्यासीकरण कितना अद्भुत है (और इससे उन्हें अपनी एक फ़िल्म को उपन्यास का रूप देने का विचार आया है!)। शूजीत सरकार ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए फ़ोन किया था।”

38. इस प्रकार, श्री दासवानी प्रस्तुत करते हैं कि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि उपन्यास उस फ़िल्म की पटकथा की प्रत्यक्ष प्रति थी जिसका प्रतिलिप्यधिकार वादी के पास था।

#### वर्तमान अंतर.आ. में सुश्री स्वाति सुकुमार के प्रस्तुतीकरण

39. श्री दासवानी को उत्तर देते हुए, सुश्री सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि सत्यजीत रे पटकथा के साथ-साथ फ़िल्म की स्क्रिप्ट का भी मालिक था और इसलिए, उसके पास इसके संबंध में प्रतिलिप्यधिकार था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वादी ने यह दावा करके मौलिक रूप से विधि की दृष्टि से गलती की है कि फ़िल्म में वादी के प्रतिलिप्यधिकार के साथ-साथ फ़िल्म में अंतर्निहित कार्यों का प्रतिलिप्यधिकार भी शामिल है। बेशक, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि फ़िल्म के किसी भी पहलू में सत्यजीत रे या किसी अन्य द्वारा वादी के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्रतिलिप्यधिकार का कोई समनुदेशन नहीं किया गया है। वादी के अनुसार, एक सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म से जुड़ी हर चीज़ के सभी अधिकार, जिसमें अंतर्निहित

कार्यों के प्रतिलिप्यधिकार के साथ-साथ फ़िल्म की तस्वीरें भी शामिल हैं, उस प्रतिलिप्यधिकार में समाहित हो जाएँगे जो फ़िल्म के निर्माता को फ़िल्म में प्राप्त हैं।

40. सुश्री सुकुमार आगे प्रस्तुत करती हैं कि, भले ही यह मान भी लिया जाए कि वादी के पास फ़िल्म की पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार है, जबकि फ़िल्म 1966 में ही रिलीज़ हुई थी, तो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 23 के तहत, प्रतिलिप्यधिकार की अवधि फ़िल्म रिलीज़ होने के तुरंत बाद के वर्ष से 50 वर्ष होगी। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करती हैं कि फ़िल्म की पटकथा में वादी का प्रतिलिप्यधिकार, भले ही अस्तित्व में हो, 2017 में समाप्त हो जाएगा और इसलिए, 2018 में अस्तित्व में नहीं रहेगा, जब फ़िल्म का उपन्यासीकरण किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, वह प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 2<sup>10</sup> पर निर्भर करती हैं।

41. सुश्री सुकुमार प्रस्तुत करती हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के साथ सहपठित धारा 13(4) वादपत्र का पूर्ण रूप से उत्तर देती है, और कार्रवाई के मूल कारण को ही ध्वस्त कर देती है जिस पर वादपत्र आधारित है।

42. साथ में, सुश्री सुकुमार ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14 पर भी भरोसा किया है, जो "प्रतिलिप्यधिकार" को परिभाषित करती है। वह प्रस्तुत करती

---

<sup>10</sup> "2. अध्याय V का संशोधन - प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अध्याय V में, "पचास वर्ष" शब्दों के लिए, जहाँ भी वे होते हैं, "साठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

हैं कि साहित्यिक कार्यों के संबंध में सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म बनाने का अधिकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14(1)(क)(v) द्वारा परिकल्पित एक अलग अधिकार है। धारा 14(1)(क) साहित्यिक, नाटकीय और संगीत कार्यों के संबंध में आठ प्रकार के प्रतिलिप्यधिकार की परिकल्पना करती है, जैसे किसी भी सामग्री रूप में कार्य को पुनरुत्पादित करने का अधिकार [खंड (i)], कार्य को प्रकाशित करने का अधिकार [खंड (ii)]; कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का अधिकार [खंड (iii)]; कार्य के किसी भी अनुवाद का उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन या प्रकाशन करने का अधिकार [खंड (iv)]; कार्य के संबंध में सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म या रिकॉर्ड बनाने का अधिकार [खंड (v)]; रेडियो-प्रसार द्वारा कार्य को संप्रेषित करने या लाउडस्पीकर या किसी अन्य समान उपकरण द्वारा कार्य के रेडियो-प्रसार को जनता तक संप्रेषित करने का अधिकार [खंड (vi)]; कार्य का कोई भी अनुकूलन करने का अधिकार [खंड (vii)] और कार्य के अनुवाद या किसी रूपांतरण के संबंध में पूर्ववर्ती खंडों में निर्दिष्ट कोई भी कार्य करने का अधिकार [खंड (viii)]। धारा 14(1)(क)(v) से संबंधित यह एकमात्र अधिकार था, जिसके बारे में अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि इसे वादी के पक्ष में सत्यजीत रे द्वारा अनुज्ञापित किया गया था। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14(1)(क) में परिकल्पित अन्य सभी अधिकार उक्त प्रावधान के आधार पर सत्यजीत रे के पास रहेंगे। वह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के खंड (ग) का भी

उल्लेख करती हैं, जो सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में रखे गए प्रतिलिप्यधिकार से उत्पन्न अधिकारों में, अंतर्निहित कार्य को उपन्यासीकरण करने के अधिकार को शामिल करने की परिकल्पना नहीं करता है। इसलिए, सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में अंतर्निहित कार्य को उपन्यासीकरण करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में मौजूद प्रतिलिप्यधिकार से स्वतंत्र है। इसलिए, सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में निर्माता का अधिकार अंतर्निहित कार्य को उपन्यासीकरण करने या, परिणामस्वरूप, अंतर्निहित कार्य के उपन्यासीकरण की निगरानी या प्रतिबंधित करने के अधिकार तक विस्तारित नहीं होता है। वह बताती हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17 के खंड (क) और (ख) के आधार पर, फ़िल्म में वादी का प्रतिलिप्यधिकार अंतर्निहित कार्य तक विस्तारित नहीं होता है। इस प्रकार, फ़िल्म के अंतर्निहित कार्य का प्रतिलिप्यधिकार, जिसमें इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा शामिल थी, हर समय स्क्रिप्ट और पटकथा के लेखक अर्थात् सत्यजीत रे के पास है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 19 के आधार पर, ऐसे अधिकार का कोई भी समनुदेशन, चाहे वह वादी के पक्ष में हो या किसी और के पक्ष में, अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होना चाहिए। सुश्री सुकुमार यह प्रस्तुत करती हैं कि अधिकार का ऐसा कोई लिखित समनुदेशन उपलब्ध नहीं है, तो वादी द्वारा स्थापित पूरा मामला अनुरक्षणीय वादहेतुक से रहित है।

43. *त्यागराजन कुमारराजा बनाम कैपिटल फिल्म वर्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड*<sup>11</sup> में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 1.3, 3.1, 4, 18.4, 19.7, 21 और 25 से 28 पर भरोसा करते हुए, सुश्री सुकुमार प्रस्तुत करती हैं कि उनके कक्षीकार का मामला वास्तव में *त्यागराजन* में न्यायालय के समक्ष आए मामले से बेहतर है, क्योंकि उनका कक्षीकार फिल्म का रीमेक नहीं बना रहा था। वह *अदाई मेहरा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुमीत पी. मेहरा*<sup>12</sup> मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 24, 28, 29, 49, 57 से 61, 67, 68 और 72, *आई.पी.आर.एस.* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 15 और 21 और *पावर कंट्रोल अप्लायंसेज बनाम सुमीत मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड*<sup>13</sup> में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 26 और 33 पर भी भरोसा करती है।

वर्तमान अंतर.आ. में श्री दासवानी का उत्तर

44. सुश्री सुकुमार की प्रस्तुतियों का उत्तर देते हुए, श्री दासवानी *श्री वेंकटेश फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड बनाम विपुल अमृतलाल शाह* और *त्यागराजन*<sup>14</sup> के पैरा 29 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसे सुश्री सुकुमार ने उद्धृत किया था। उन्होंने आगे कहा कि, चूँकि उपन्यास की कहानी फिल्म के

<sup>11</sup> (2018) 73 पीटीसी 365(मद्रास)

<sup>12</sup> (2014) 59 पीटीसी 575(बॉम्बे)

<sup>13</sup> (1994) 2 एससीसी 448

<sup>14</sup> 2009 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 2113

समान है, उपन्यास प्रभावी रूप से फ़िल्म की एक नकल है। इसलिए, यह फ़िल्म ही थी, जिसे कलम और कागज़ में परिवर्तित किया जा रहा था। फ़िल्म के दर्शक और उपन्यास के पाठक को बताए गए विचार के बीच कोई अंतर नहीं होगा। उनकी प्रस्तुति है कि "नकल" शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, श्री दासवानी ने *ट्विन पीक्स प्रोडक्शंस बनाम पब्लिकेशन इंटरनेशनल*<sup>15</sup> और *मिराज एडिशन बनाम अल्बुकर्क ए.आर.पी. कंपनी*<sup>16</sup> में यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ़ अपीलस के निर्णयों को उद्धृत किया है। उनकी प्रस्तुति है कि वर्तमान मामला भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नकल करने का है। श्री दासवानी ने *आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फ़िल्म्स*<sup>17</sup> में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 19, 34 और 46 और *एम.आर.एफ. लिमिटेड बनाम मेट्रो टायर्स लिमिटेड*<sup>18</sup> में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के पैरा 78 और 79 पर भी भरोसा किया है।

45. इस प्रकार, श्री दासवानी का कहना है कि प्रतिवादी के वर्तमान आवेदन में कोई बल नहीं है और वास्तव में, वह उसके द्वारा माँगे गए अंतर्वर्ती व्यादेश का हकदार होगा।

अंतर.आ. में सुश्री सुकुमार का प्रत्युत्तर

---

<sup>15</sup> 61 यूएस एलडब्ल्यू 2784

<sup>16</sup> 856 एफ़.2डी 1341 (1988)

<sup>17</sup> (1978) 4 एससीसी 118

<sup>18</sup> 2019 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 8973

46. प्रत्युत्तर में, सुश्री सुकुमार बताती हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत, सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में फ़िल्म के मालिक के अधिकार साहित्यिक कार्य में प्रतिलिप्यधिकार धारक के अधिकार से बहुत कम हैं। वह प्रस्तुत करती हैं कि *आर.जी. आनंद* मामले में निर्णय को उल्टा नहीं पढ़ा जा सकता। यदि कृति के लेखक से अनुज्ञप्ति के बिना साहित्यिक कृति को फ़िल्म में परिवर्तित किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से अतिलंघन का परिणाम होगा।

## विश्लेषण

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. का आदेश XIII-क

47. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. का आदेश XIII-क, वाणिज्यिक न्यायालय को मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना वाणिज्यिक विवाद से संबंधित दावे पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। आदेश XIIIक के नियम (2)(क)<sup>19</sup> के आधार पर, "दावा" शब्द में दावे का हिस्सा भी शामिल है।

---

<sup>19</sup> (2) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, "दावा" शब्द में शामिल होंगे -

(क) दावे का भाग;

48. जिन आधारों पर न्यायालय द्वारा संक्षिप्त निर्णय दिया जा सकता है, वे आदेश XIII नियम 3<sup>20</sup> में निर्धारित किए गए हैं।

49. आदेश XIII नियम 3 का खंड (क) न्यायालय को किसी भी पक्ष के खिलाफ संक्षिप्त निर्णय देने का अधिकार देता है, यदि वह मानता है कि पक्ष के पास उसके द्वारा स्थापित मामले में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, अर्थात्, वादी के पास दावे पर सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी के पास दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। खंड (ख) व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है क्योंकि यह न्यायालय को मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना किसी दावे का निपटान करने का अधिकार देता है, यदि कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं है कि दावे का निपटान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

50. आदेश XIII-क का उद्देश्य और प्रयोजन उसके नियम 1 के उप-नियम 3(ख) से स्पष्ट हो जाता है। वाणिज्यिक वादों का शीघ्र निपटान स्पष्ट रूप से आदेश XIII-क का मुख्य प्रयोजन है। आदेश XIII-क नियम 3(ख) एक विचित्र

---

<sup>20</sup> 3. संक्षिप्त निर्णय के लिए आधार - न्यायालय एक दावे पर एक वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध एक संक्षिप्त निर्णय दे सकता है यदि वह मानता है कि -

(क) वादी के पास दावे पर सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी के पास दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, जैसा भी मामला हो; और

(ख) मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करने से पूर्व दावे का निपटान न किए जाने का कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं है।



शब्दों वाला प्रावधान है, जिसमें एक दिलचस्प दोहरा नकारात्मक पहलू है। यह न्यायालय को मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना किसी वाणिज्यिक वाद पर संक्षिप्त निर्णय लेने का अधिकार देता है, जहाँ ऐसा न करने का कोई बाध्यकारी कारण उपस्थित नहीं है। इसलिए, मौखिक साक्ष्य को रिकॉर्ड करना किसी भी तरह से वाणिज्यिक वादों के अधिकार में नहीं है। एक न्यायालय, अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना वाद का निपटान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

51. हालाँकि, आदेश XIII-क नियम 4 के अनुसार, किसी वाणिज्यिक वाद में दावे के किसी भी हिस्से का निर्णय करने वाले न्यायालय द्वारा संक्षिप्त निर्णय पारित करने से पहले एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। उक्त प्रयोजन हेतु एक आवेदन पत्र आवश्यक है। आवेदन पर सुनवाई करने और प्रत्यर्थी/गैर-आवेदक को दावे के नोटिस पर रखने से पहले प्रतिवादी को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिस पर वह ऐसी सुनवाई में निर्णय लेने का प्रस्ताव करता है। गैर-आवेदक संक्षिप्त निर्णय की माँग करते हुए आवेदन का उत्तर दाखिल कर सकता है और उत्तर, यदि कोई हो, दाखिल होने और पक्षकारगण को सुनने के बाद ही न्यायालय आदेश XIIIक के तहत सारांश निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

52. वर्तमान मामले में, सुश्री सुकुमार का तर्क यह है कि, तथ्यात्मक और विधिक स्थिति को देखते हुए, वादी की वाद में प्रार्थना (क) में सफल होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, वह प्रार्थना करती हैं कि वाद में प्रार्थना (क) को खारिज करने वाला संक्षिप्त निर्णय पारित किया जा सके।

53. वाद में प्रार्थना खंड इस प्रकार है:

“34. इन परिस्थितियों में, वादी निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है:

क. प्रतिवादी को स्वयं या उसके डीलरों, वितरकों, थोक व्यापारियों, एजेंटों, सहयोगियों, सहयोगी संस्थाओं, कर्मचारियों, नौकरों और/या नियुक्तियों के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म 'नायक' के संबंध में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्युत्पन्न फिल्म/स्क्रिप्ट के उपन्यासीकरण में शामिल किसी भी कार्य को बनाने, बेचने, बिक्री के लिए पेश करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री, जो वादी के प्रतिलिप्यधिकारी का अतिलंघन है;

ख. प्रतिवादी को स्वयं या उसके डीलरों, वितरकों, थोक व्यापारियों, एजेंटों, सहयोगियों, सहयोगी संस्थाओं, कर्मचारियों, नौकरों और/या नियुक्तियों के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म नायक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी फिल्म की स्थिर तस्वीरों को बनाने, बेचने, बिक्री के लिए पेश करने, विज्ञापन करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश का डिक्री, जो वादी के प्रतिलिप्यधिकारी का अतिलंघन है;

ग. सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म नायक के संबंध में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्युत्पन्न फिल्म/स्क्रिप्ट के उपन्यासीकरण में शामिल होने सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कार्य को बेचने, बिक्री की पेशकश करने, विज्ञापन करने से प्रतिवादी द्वारा अर्जित धन/लाभ/पारिश्रमिक का हिसाब देने का निर्देश देने वाले आदेश;

घ. प्रतिवादी के ऐसे गलत कृत्यों के कारण वादी को हुए नुकसान की जाँच करने के लिए एक जाँच की डिक्री और ऐसी जाँच पर प्रतिवादी द्वारा वादी को देय राशि के भुगतान के लिए एक डिक्री पारित की जाएगी;

ङ प्रतिवादी के खिलाफ़ और वादी के पक्ष में, बिक्री, बिक्री की पेशकश, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना, जिसमें सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म नायक के संबंध में फिल्म/स्क्रिप्ट के उपन्यासीकरण में शामिल होना शामिल है, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्युत्पन्न हो, के कारण दो करोड़ रुपये (2,00,00,000/- रुपये) की नुकसान के लिए डिक्री पारित करें;

च. वादी के पक्ष में कार्यवाही के जुमाने की अनुमति दें; और

छ. इस माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ठीक और उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य या आगे आने वाले आदेशों को भी प्रतिवादी के खिलाफ़ और वादी के पक्ष में पारित किया जा सकता है।"

**54.** वाद में प्रार्थना (क) प्रतिवादी और उसकी ओर से काम करने वाले सभी अन्य लोगों के खिलाफ़ फिल्म "नायक" के संबंध में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न फिल्म/स्क्रिप्ट के उपन्यासीकरण सहित किसी भी कार्य को बनाने, बेचने, बिक्री

की पेशकश करने या विज्ञापन करने से व्यादेश की माँग करती है, जो कि वादी के प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन होगा।

55. यह किसी का मामला नहीं है कि प्रतिवादी फ़िल्म "नायक" का उपन्यास बना रहा है। वास्तव में, यह सख्ती से कहा जा रहा है, यह वादी का मामला भी नहीं कि प्रतिवादी फ़िल्म की स्क्रिप्ट का उपन्यास बना रहा है। विद्वान अधिवक्ता का एक मत है कि प्रतिवादी फ़िल्म की पटकथा का उपन्यास बना रहा है। वादपत्र का पैरा 5(क) (पूर्वोक्त में पुनरुत्पादित) स्वयं ही किसी फ़िल्म की पटकथा और स्क्रिप्ट के बीच अंतर करता है। इस प्रकार, यहाँ तक कि वादपत्र में किए गए प्राख्यानों और वादी द्वारा उठाए जाने वाले मामले में भी, प्रतिवादी को फ़िल्म, या फ़िल्म "नायक" की स्क्रिप्ट को उपन्यास का रूप देने से रोकने का प्रश्न, विचार के लिए नहीं उठता है।

56. न्यायालय को यह तय करना है कि क्या प्रतिवादी को वादी की अनुमति के बिना फ़िल्म नायक की पटकथा को उपन्यास का रूप देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस तरह का उपन्यासीकरण वादी के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन है, तो यह स्पष्ट है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि, हालाँकि, ऐसा कोई अतिलंघन नहीं है, तो वादी वादपत्र की प्रार्थना 34(क) के संदर्भ में व्यादेश की माँग नहीं कर सकता है और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी उक्त प्रार्थना को खारिज करने वाले संक्षिप्त निर्णय का हकदार होगा।

57. तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। यह बात दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की गई है कि (i) वादी फ़िल्म "नायक" का निर्माता है, (ii) वादी ने फ़िल्म की पटकथा लिखने के लिए सत्यजीत रे के साथ संविदा की थी, (iii) पटकथा पूरी तरह सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई थी, (iv) संदीप रे सत्यजीत रे का बेटा है और एस.पी.एस.आर.ए. का सदस्य है (v) प्रतिवादी ने फ़िल्म का उपन्यासीकरण करने से पहले वादी से कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की थी।

58. ये तथ्य निर्विवाद हैं, और न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या इन तथ्यों के आधार पर, प्रतिवादी के बारे में कहा जा सकता है कि उसने वादी के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया है, वर्तमान मामले में मौखिक साक्ष्य पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मामला स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XIII-क नियम 3(ख) के अंतर्गत आता है।

#### गुणागुण के आधार पर

59. जहाँ तक परस्पर विरोधी विवादों के गुणागुण का प्रश्न है, मेरी राय है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में भी उन्हें आसानी से तय किया जा सकता है।

60. धारा 13

**60.1** धारा 13(1) उन कार्यों से संबंधित है जिनमें प्रतिलिप्यधिकार विद्यमान है। उक्त उपधारा के खंड (क) में "मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्य" शामिल हैं, जबकि खंड (ख) में "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्में" शामिल हैं। स्पष्ट रूप से, इसलिए, सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्मों का प्रतिलिप्यधिकार, प्रतिलिप्यधिकार की एक भिन्न श्रेणी है, जो मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के प्रतिलिप्यधिकार से अलग और पृथक है।

**60.2** इसलिए, सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व कानूनी रूप से धारा 13(1)(ख) द्वारा परिकल्पित है। इसलिए, वादी के पास फ़िल्म नायक पर स्पष्ट रूप से प्रतिलिप्यधिकार है।

**60.3** धारा 13 की उपधारा (4) स्पष्ट करती है कि सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में रखा गया प्रतिलिप्यधिकार किसी भी कार्य के भिन्न प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके संबंध में, या जिसके एक बड़े हिस्से के संबंध में, फ़िल्म बनाई गई है। दूसरे शब्दों में, *यदि कोई सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म संपूर्ण या किसी अन्य कार्य के एक भाग के संबंध में बनाई गई है जिसमें धारा 13(1) के तहत भिन्न प्रतिलिप्यधिकार निहित हैं, तो सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म में रखा गया प्रतिलिप्यधिकार ऐसे भिन्न प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।*

**60.4 समय के बीत जाने पर प्रतिलिप्यधिकार की समाप्ति के बारे में सुश्री सुकुमार का पुनर्प्रस्तुतीकरण:**

**60.4.1** आगे बढ़ने से पहले, मैं इस संदर्भ में, सुश्री सुकुमार की इस प्रस्तुति पर चर्चा करूँगा कि फ़िल्म नायक में वादी का प्रतिलिप्यधिकार समय के साथ समाप्त हो गया है। वह उक्त उद्देश्य के लिए, प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 ( इसके बाद "1993 संशोधन अधिनियम") की धारा 2 पर निर्भर करती हैं।

**60.4.2** 1993 के संशोधन अधिनियम ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में काफ़ी संशोधन किया। धारा 2 ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (जो प्रतिलिप्यधिकार के जीवन से संबंधित है) के अध्याय V में "पचास वर्ष" शब्दों को "साठ वर्ष" शब्दों से बदल दिया। इस प्रकार प्रतिलिप्यधिकार का जीवन पचास से बढ़ाकर साठ वर्ष कर दिया गया। सुश्री सुकुमार ने तर्क दिया कि, चूँकि प्रतिलिप्यधिकार की अवधि में यह वृद्धि एक संशोधन द्वारा प्रभावित हुई थी, जो फ़िल्म "नायक" में वादी के प्रतिलिप्यधिकार के शुरू होने के बाद हुआ था, तो वादी इसके लाभ का हकदार नहीं होगा।

**60.4.3** मेरे विचार से यह प्रस्तुति गलत है। 1993 के संशोधन अधिनियम की धारा 3<sup>21</sup> - जिसका शीर्षक "यदि अवधि समाप्त हो गई है तो प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में नहीं रहेगा" है, जिसमें "नहीं रहेगा" शब्दों पर असामान्य रूप से इटैलिक करके ज़ोर दिया गया है - संदेह को दूर करने के लिए घोषणा करती है कि प्रतिलिप्यधिकार 1993 संशोधन अधिनियम के आधार पर किसी भी कार्य में मौजूद नहीं रहेगा जिसमें प्रतिलिप्यधिकार 1993 संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले अस्तित्व में नहीं था ज़ाहिर है, परिणाम यह होगा कि, जहाँ संबंधित कार्य में प्रतिलिप्यधिकार 1993 संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले समाप्त नहीं हुआ था, वह अस्तित्व में रहेगा, और प्रतिलिप्यधिकार धारक संशोधन के लाभ का हकदार होगा। वादी के पक्ष में फ़िल्म का प्रतिलिप्यधिकार, 1993 के संशोधन अधिनियम से ठीक पहले से मौजूद था। इसलिए, वादी को 1993 संशोधन अधिनियम की धारा 2 के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, फ़िल्म नायक में वादी द्वारा रखे गए प्रतिलिप्यधिकार का जीवन 1967 से 60 वर्ष होगा जो केवल 2027 में समाप्त होगा।

---

<sup>21</sup> 3. यदि अवधि समाप्त हो गई है तो प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में नहीं रहेगा। - संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार इस अधिनियम के आधार पर किसी भी कार्य में मौजूद नहीं होगा जिसमें प्रतिलिप्यधिकार इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले मौजूद नहीं था।



**60.4.4** सुश्री सुकुमार का अभिवचन कि फ़िल्म नायक में वादी का प्रतिलिप्यधिकार धारा 2 के आधार पर समाप्त हो गया है, इसलिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

**60.4.5** इसलिए, आज की तिथि में भी सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म "नायक" पर वादी का प्रतिलिप्यधिकार कायम है।

**60.5** उस पृष्ठभूमि में, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 13 पर लौटते हुए, जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या फ़िल्म "नायक" की पटकथा में कोई भिन्न प्रतिलिप्यधिकार मौजूद है, जो फ़िल्म में वादी द्वारा रखे गए प्रतिलिप्यधिकार से असंबद्ध है। यदि ऐसा होता है, तो धारा 13(4) के आधार पर, फ़िल्म में वादी द्वारा रखा गया प्रतिलिप्यधिकार उस भिन्न प्रतिलिप्यधिकार से कम नहीं हो सकता जो फ़िल्म की पटकथा में मौजूद है।

**60.6** इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि फ़िल्म की पटकथा पूरी तरह सत्यजीत रे की देन है। वादी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। दरअसल, हालाँकि यह तथ्य खास प्रासंगिक नहीं है, यहाँ तक कि फ़िल्म "नायक" भी पूरी तरह से सत्यजीत रे की निर्देशन मेहनत था। वादी केवल फ़िल्म का निर्माता है।

**60.7** इसलिए, देखने वाली बात यह है कि क्या किसी फ़िल्म की पटकथा धारा 13(1) को आकर्षित करती है।

**60.8** धारा 13 की उपधारा (1) उन कार्यों के संबंध में विस्तृत है जिनमें प्रतिलिप्यधिकार विद्यमान है। धारा 13(1) के बाहर किसी भी कार्य में कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं रह सकता।

**60.9** धारा 13(1) का खंड (क) "मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों", खंड (ख) "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्मों" और खंड (ग) "अभिलेख" में प्रतिलिप्यधिकार के अस्तित्व को प्रदान करता है।

**60.10** दिलचस्प बात यह है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम धारा 2 के खंड (ग)<sup>22</sup> और (त)<sup>23</sup> में "कलात्मक कार्य" और "संगीत कार्य" शब्दों की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है, लेकिन उक्त धारा के खंड (ण)<sup>24</sup> और (ज)<sup>25</sup> में "साहित्यिक कार्य" और "नाटकीय कार्य" शब्दों के लिए केवल समावेशी परिभाषा प्रदान करता है।

---

<sup>22</sup> (ग) "कलात्मक कृति" से अभिप्रेत है -

(i) कोई रंगचित्र, मूर्ति, रेखाचित्र (जिसके अन्तर्गत आरेख, मानचित्र, चार्ट या रेखांक भी हैं), कोई उत्कीर्ण या फोटोग्राफ, चाहे ऐसी किसी कृति में कलात्मक गुण हो या न हो;

(ii) कोई [वास्तु कृति]; और

(iii) कलात्मक शिल्पकारिता की कोई अन्य कृति

<sup>23</sup> (त) "संगीतात्मक कृति" से संगीत से संयोजित कोई कृति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी कृति का कोई आलेखनीय स्वरांकन है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे कोई शब्द या ऐसा कोई कार्य नहीं आता है जो संगीत के साथ गाने, बोलने या प्रस्तुत करने के लिए आशयित है;

<sup>24</sup> (ण) "साहित्यिक कृति" के अंतर्गत सारणियां और संकलन हैं;

<sup>25</sup> (ज) "नाट्यकृति" के अंतर्गत सुपठन के लिए रचनांश, नृत्यरचनाकृति या मूक प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन भी है जिसका दृश्य विन्यास या अभिनय का रूप लिखित रूप में या अन्यथा नियत है किन्तु इसके अंतर्गत चलचित्र फिल्म नहीं है;

**60.11** स्पष्ट रूप से, फ़िल्म नायक की पटकथा को "कलात्मक कार्य" या "संगीतमय कार्य" के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि धारा 2 के खंड (ग) और (त) में परिभाषित किया गया है।

**60.12** धारा 2(ज) में "नाटकीय कार्य" की परिभाषा स्पष्ट रूप से सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्मों को बाहर करती है। फिर भी, फ़िल्म की पटकथा परिभाषा में शामिल करने योग्य नहीं होगी क्योंकि इसे "मूंग शो में गायन, कोरियोग्राफी कार्य या अनुवाचन के संचय" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

**60.13** "साहित्यिक कार्य" को धारा 2(ण) में "सारणी और संकलन" सहित समावेशी ढंग से परिभाषित किया गया है।

**60.14** कानूनी साधनों में, परिभाषा खंडों की व्याख्या, जो पूरी तरह से समावेशी अभिव्यक्तियों में शामिल हैं, कई न्यायिक उद्घोषणाओं का विषय रही हैं। *महाराष्ट्र राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड*<sup>26</sup> मामले में, उच्चतम न्यायालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 3 (क) से चिंतित था, जिसमें कहा गया था कि "भूमि में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, धरती से जुड़ी हुई चीज़ें या धरती से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीज़ें शामिल हैं"। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ कोई कानून एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है "शब्द न केवल अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक

---

<sup>26</sup> (2017) 10 एससीसी 713

अर्थ को धारण करता है, जब भी वह लागू होगा, बल्कि यह अपने विस्तारित कानूनी अर्थ को भी धारण करता है"। "शामिल है" शब्द का उपयोग *रमाला सहकारी चीनी मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त*<sup>27</sup> के मामले में किया गया था, जिसका उद्देश्य "विधिक कल्पना द्वारा, मूल भाग के स्वीकृत अर्थ के भीतर कुछ लाना" था। इसी तरह, *ओसवाल ऑयल्स एंड फ़ैट्स लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त*<sup>28</sup> मामले में, यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 154(1) में परिभाषित "व्यक्ति" अभिव्यक्ति की व्याख्या से निपटते समय, जिसने "व्यक्ति" को "किसी भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्ति के निकाय सहित, चाहे निगमित हो या नहीं" उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"शब्द "शामिल" का प्रयोग आम तौर पर कानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाने के लिए व्याख्या खंडों में किया जाता है और जब इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है तो उन शब्दों या वाक्यांशों को समझने योग्य माना जाना चाहिए, न केवल ऐसी चीज़ें, जैसा कि वे अपने प्राकृतिक आयात के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि वे चीज़ें भी जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे उनमें शामिल होंगे।

शब्द "शामिल" एक अन्य निर्माण के लिए अतिसंवेदनशील है, जो अनिवार्य हो सकता है, यदि अधिनियम का संदर्भ यह दिखाने के

---

<sup>27</sup> (2010) 14 एससीसी 744

<sup>28</sup> (2010) 4 एससीसी 728

लिए पर्याप्त है कि इसका प्रयोग केवल इस्तेमाल किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक महत्व को जोड़ने के उद्देश्य से नहीं किया गया था।

यह "आशय और शामिल" के समतुल्य हो सकता है और उस स्थिति में यह उस अर्थ की एक विस्तृत व्याख्या प्रदान कर सकता है जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन शब्दों या अभिव्यक्तियों के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए।  
(दिलवर्थ बनाम स्टैम्प्स आयुक्त<sup>29</sup>)"

**60.15** इस प्रकार, एक समावेशी परिभाषा में "शामिल" के बाद आने वाले शब्द सामान्य रूप से समझे जाने वाले अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाकर परिभाषा का विस्तार करते हैं। किसी अभिव्यक्ति की समावेशी परिभाषा में "शामिल" के बाद आने वाले शब्द, जैसा कि एक कानूनी साधन में निहित है, इसलिए, किसी भी तरह से आम बोलचाल में परिभाषा के मुख्य भाग की सामान्य समझ के दायरे को प्रतिबंधित या सीमित नहीं कर सकते हैं।

**60.16** अभिव्यक्ति "साहित्यिक कार्य" को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (ण) में एक समावेशी ढंग से परिभाषित किया जा रहा है, इसलिए, इसके दायरे में, अभिव्यक्ति "साहित्यिक कार्य" की सामान्य व्युत्पत्ति संबंधी समझ को शामिल

---

<sup>29</sup> 1899 एसी 99 : (1895-99) ऑल ईआर रेप एक्स्ट 1576 (पीसी)

करना होगा, और इसमें आम तौर पर साहित्यिक कृति समझी जाने वाली चीज़ों के अलावा तालिकाएँ और संकलन भी शामिल होंगे।

**60.17** हालाँकि, "साहित्यिक कार्य" अभिव्यक्ति को कैसे समझा जाए, इस संबंध में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

**60.18** न्यायालयों ने "साहित्यिक कार्य" अभिव्यक्ति की काफी व्यापक समझ अपनाई है। *रूपेंद्र कश्यप बनाम जीवन पब्लिशिंग हाउस*<sup>30</sup> के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "साहित्यिक कार्य" शब्द आम तौर पर समझे जाने वाले अर्थ में साहित्य के कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें लिखित रूप में व्यक्त सभी कार्य शामिल हैं, चाहे उनमें साहित्यिक गुणागुण हो या नहीं। इस प्रकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा प्रश्नपत्रों को मूल साहित्यिक कृतियाँ अभिनिर्धारित किया गया। *बर्लिंगटन होम शिपिंग (प्रा.) लिमिटेड बनाम रजनीश छिबर*<sup>31</sup> मामले में, यह न्यायालय "साहित्यिक कार्य" अभिव्यक्ति के दायरे में, आम तौर पर उपलब्ध स्रोतों से भी समय, धन, श्रम और कौशल समर्पित करके किसी व्यक्ति द्वारा विकसित क्लाइंट या ग्राहकों की एक सूची का संकलन शामिल करने की सीमा तक चला गया। *श्री मनोहर लाल गुप्ता*

---

<sup>30</sup> (1976) पीटीसी 439 (दिल्ली)

<sup>31</sup> 61 (1996) डीएलटी 6

**बनाम हरियाणा राज्य<sup>32</sup>** मामले में, इस न्यायालय ने "साहित्यिक कार्य", घरेलू खातों और घरेलू अंकगणित की पुस्तकों को शामिल किया।

**60.19** "साहित्यिक कार्य" अभिव्यक्ति के दायरे को देखते हुए, मेरे विचार से, इस तथ्य के बारे में थोड़ा संदेह हो सकता है कि फ़िल्म नायक की पटकथा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 13(1)(क) के प्रयोजन के लिए निर्विवाद रूप से एक "साहित्यिक कार्य" है।

**60.20** तदनुसार, धारा 13(4) के परिचालन से, पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार, एक "साहित्यिक कार्य" के रूप में, जो धारा 13(1)(क) द्वारा निहित है, सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के भिन्न प्रतिलिप्यधिकार से प्रभावित नहीं हो सकता है, जो निर्विवाद रूप से, इसके निर्माता के रूप में वादी के पास है।

**61.** फ़िल्म की पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास है?

**61.1** तो फिर, "साहित्यिक कार्य", जिसमें फ़िल्म "नायक" की पटकथा शामिल है, का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास होगा? यह अगला और वास्तव में, एक मौलिक प्रश्न है जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उठता है।

**61.2** धारा 17 उत्तर प्रदान करती है।

---

<sup>32</sup> (1996) 61 डीएलटी 6

**61.3** धारा 17 के शुरुआती शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि *किसी कार्य का लेखक उस कार्य में प्रतिलिप्यधिकार का पहला स्वामी होगा।* यह केवल (i) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्य प्रावधानों और (ii) धारा 17 के परंतुक के अधीन है।

**61.4** कुछ हद तक घुमावदार ढंग से, "लेखक" को एक साहित्यिक कार्य के संबंध में, धारा 2(घ)(i) में, "कार्य के लेखक" के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः फिल्म "नायक" की पटकथा के लेखक निर्विवाद रूप से सत्यजीत रे ही हैं।

**61.5** यह किसी का मामला नहीं है कि धारा 17 के अलावा कोई प्रावधान है, जो फिल्म नायक की पटकथा में किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिलिप्यधिकार प्रदान करेगा। दरअसल, वादी भी धारा 17 के परंतुक को लागू करना चाहता है।

**61.6** धारा 17 के परंतुक में, जैसा कि उस समय था, चार खंड थे, क्रमांकित (क), (ख), (ग), और (घ)।

**61.7** परंतुक का खंड (क) किसी समाचार पत्र, पत्रिका या इसी तरह के आवधिक के मालिक द्वारा अपने रोज़गार के दौरान लेखक द्वारा किए गए साहित्यिक, नाटकीय या कलात्मक कार्य को संदर्भित करता है और ज़ाहिर है, इसलिए, यह लागू नहीं होगा।



**61.8** खंड (ख) में किसी व्यक्ति के कहने पर ली गई तस्वीर, बनाई गई पेंटिंग या चित्र या उत्कीर्णन या सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म शामिल है। इसलिए, यह खंड भी पटकथा को कवर नहीं करता है। उक्त खंड में "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म" का संदर्भ केवल उस स्थिति पर लागू होता है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने पर सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म बनाता है। स्पष्टतया, यह ऐसी स्थिति नहीं है जो हमारे समक्ष है।

**61.9** खंड (ग) सेवा या शिक्षता के अनुबंध के तहत लेखक के रोज़गार के दौरान किए गए कार्य से संबंधित है। यह खंड भी दो कारणों से लागू नहीं होगा:

- (i) "सेवा" और "शिक्षता" शब्दों का एक साथ उपयोग किए जाने पर उनकी साहचर्येण ज्ञायते व्याख्या की जानी चाहिए, जिसके लिए किसी शब्द के अर्थ को उस संबंधित विषयों के प्रकाश में समझने की आवश्यकता होती है जिसमें वह प्रयोग होता है। इसलिए, धारा 17 के परंतुक के खंड (ग) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सेवा" शिक्षता के अनुरूप सेवा होगी। "शिक्षता" में काम पर रखने का सिद्धांत और मालिक-नौकर संबंध का अस्तित्व शामिल है। पी. रामनाथ अय्यर, अपने आधिकारिक एडवांस लॉ लेक्सिकन के 5वें संस्करण में "शिक्षता" को "किसी शिक्षु की सेवा या कानूनी स्थिति, किसी मास्टर के निर्देश से किसी व्यापार, कला या पेशे

का ज्ञान प्राप्त करने की विधि या प्रक्रिया; वह अवधि जिसके दौरान कोई शिक्षु होता है।" इसलिए, स्वामी-सेवक संबंध का अस्तित्व शिक्षुता की अनिवार्य शर्त है। "शिक्षुता" के संबंध में उपयोग की जा रही अभिव्यक्ति "सेवा" को शिक्षुता के अनुरूप समझा जाना चाहिए, और साहचर्येण ज्ञायते को एक सामाजिक सिद्धांत लागू करना चाहिए। इस प्रकार, सेवा की संविदा शिक्षुता के संविदा के अनुरूप होगा, जो मालिक और नौकर के बीच एक रोज़गार संविदा है।

(ii) यह निष्कर्ष इस तथ्य से भी समर्थित है कि कानून "सेवा की संविदा" और "सेवा के लिए संविदा" के बीच की परिभाषा को मान्यता देता है। इन दोनों अभिव्यक्तियों के बीच की परिभाषा को *सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम न्यू एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*<sup>33</sup> में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में आधिकारिक रूप से समझाया गया है। उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश उस संबंध में विधि की व्याख्या करते हैं। निर्णय के पैरा 32 से 36 को इस प्रकार पुनःप्रस्तुत किया जा सकता है:

“32. सभी उपरोक्त निर्णयों का निचोड़ यह है कि उस समाज में जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से बढ़कर जटिल आधुनिक कम्प्युटर युग में पहुँच चुका है वहाँ नियंत्रण

---

<sup>33</sup> (2021) 7 एससीसी 151

निर्धारण करने के पुराने मापदंड, जो यह निर्धारित कर सकें कि संविदा 'रोज़गार की संविदा' है या 'रोज़गार के लिए संविदा' है, और जटिल हो गए हैं। प्रारंभिक नियोक्ता का नियंत्रण जाचने का मापदंड न केवल किसी कर्मचारी द्वारा किए गए काम तक सीमित है बल्कि इसमें वह काम किस प्रकार किया जाएगा उस पर नियंत्रण भी शामिल है। यह कई सारे उदाहरणों से स्पष्ट होता है - जैसे कि स्कूल का एक मास्टर जो कि स्कूल के अन्य कर्मचारियों की तरह ही आजीविका कमाने के लिए संगीत सिखाता है और इसके मुकाबले एक स्वतंत्र पेशेवर पियानोवादिका जो अपने घर पर ही संगीत सिखाती है। समान रूप से, समुद्री जहाज़ का मालिक, किसी का निजी ड्राइवर और किसी समाचारपत्र का संवाददाता के मुकाबले कोई समुद्री जहाज़ का चालक, कोई टैक्सी चालक और समाचारपत्र में योगदान देने वाला जैसे कई उदाहरण यह जाँचने के लिए देखे जा सकते हैं कि क्या कोई कार्यरत व्यक्ति नौकरीपेशा है या स्वतंत्र पेशेवर है। नियंत्रण का मूल्यांकन - जो कि कार्य कब और कैसे किया जाना पर वास्तविक नियंत्रण से नियंत्रण करने के अधिकार तक जैसे घटकों का उपयोग कर मामले के तथ्यों को उजागर कर सकता है और मामले को 'रोज़गार की संविदा' या 'रोज़गार के लिए संविदा' में विभाजित कर सकता है। यह जानकारी कि यदि कर्मचारी नियोक्ता के कार्यकाज का अभिन्न हिस्सा है या मात्र एक सहायक, भी संविदा के स्वरूप को समझने में सहायक है। विदेशी निर्णयों

द्वारा दिया गया त्रिस्तरीय मापदंड - क्या भत्ता या अन्य मेहताना का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, क्या नियोक्ता उपयुक्त नियंत्रण है, और अन्य घटक कई सारे मामलों पर लागू हो सकते हैं। कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर स्वामित्व किसका है या आखिर में लाभ या हानि किसको हो रही है, यह निर्धारित करने में उपयोगी जानकारी है कि क्या व्यवसाय नियोक्ता के लिए चलाया जा रहा है या कर्मचारी के लिए और यह स्वतंत्र ठेकेदार और दिहाड़ी मज़दूर के बीच अंतर करता है। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था की यथार्थता का मापदंड जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निर्णयों पर आधारित हैं और यह मूल्यांकन कि क्या नियोक्ता का कर्मचारी के मेहनताना, कौशल और और उसके रोज़गार में बने रहने पर नियंत्रण है या नहीं भी यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई कर्मचारी अपने खुद के लिए काम कर रहा है या अपने नियोक्ता के लिए। *लि टिंग सांग बनाम चंग चि-कोंग*<sup>34</sup> मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित मूल्यांकन जो यह जाँचता है कि क्या कोई कार्यरत व्यक्ति स्वयं अपने लिए काम कर रहा है, भी कार्यरत व्यक्ति की दृष्टि से सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। कोई भी ऐसा सर्वव्यापी मूल्यांकन नहीं है जो सभी मामलों में सही नतीजे तक पहुँचाए। मौजूदा स्थिति में कई मूल्यांकन मिलकर निर्धारित करेंगे कि क्या संविदा को 'रोज़गार की संविदा'

<sup>34</sup> (1990) 2 एसी 374 (पीसी)

माना जाए या 'रोज़गार के लिए संविदा'। हर मामले में उपरोक्त घटक प्रासंगिक नहीं होंगे या उन सबको समान रूप से महत्व नहीं दिया जाएगा। अंत में न्यायालय सभी प्रासंगिक घटकों को नाप-तोलकर देखेगा कि क्या वह सभी एक ही तरह इशारा कर रहे हैं या फिर अलग-अलग दिशा में, ताकि हर मामले में सही निष्कर्ष तक पहुँचा जा सके।

33. इस तथ्य को देखते हुए कि यह संतुलन प्रक्रिया अक्सर मिश्रित स्थितियों में स्पष्ट परिणाम नहीं दे सकती है, जिस संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाना है वह बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार, यदि संदर्भ समाज के कमज़ोर वर्गों पर लागू होने वाले लाभकारी विधान में से एक है, तो संतुलन संविदा को सेवा में से एक घोषित करने के पक्ष में झुकता है, जैसा कि *धारंगधरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य*<sup>35</sup>, *बिरधीचंद शर्मा बनाम सिविल न्यायाधीश*<sup>36</sup>, *डी.सी. दीवान मोहिदीन साहिब एंड संस बनाम यूनाइटेड बीड़ी वर्क्स यूनियन*<sup>37</sup>, *सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस बनाम दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का मुख्य निरीक्षक*<sup>38</sup>, *हुसैनभाई बनाम अलथ फ़ैक्ट्री थेज़िलाली यूनियन, शाइनिंग टेलर्स बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल*<sup>39</sup>, *पी.एम. पटेल एंड संस*

<sup>35</sup> 1957 एलसीआर 152 : एआईआर 1957 एसी 264

<sup>36</sup> (1961) 3 एससीआर 161 : AIR 1961 एससी 644

<sup>37</sup> (1964) 7 एससीसी 646 : एआईआर 1966 एससी 370

<sup>38</sup> (1974) 3 एससीसी 498 : 1974 एससीसी (एल एंड एस) 31

<sup>39</sup> (1983) 4 एससीसी 464 : 1983 एससीसी (एल एंड एस) 533

**बनाम भारत संघ<sup>40</sup> और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बनाम सिंडिकेट बैंक के कर्मचारी<sup>41</sup>**, में किया गया था। दूसरी ओर, जहाँ संदर्भ लाभकारी विधान के अलावा या केवल संविदा के दायरे में विधान का है, और उस विधान या संविदा का संदर्भ उस संबंध की दिशा में सेवा के लिए संविदा होने की ओर इशारा करेगा, अन्य चीजें समान होने पर, संदर्भ तब संतुलन को उस संविदा के पक्ष में झुका सकता है जिसे सेवा के लिए माना जा रहा है।

34. इस आलोक में देखते हुए, आइए अब डॉ अल्पेश गांधी और प्रत्यर्थी 3 के बीच अनुबंध की जाँच करें। सेवा के लिए संविदा को एक करने वाले कारकों को निम्नानुसार गिना जा सकता है:

34.1. संविदा के शीर्षक में ही कहा गया है कि यह सेवा के लिए एक संविदा है।

34.2. डॉ. गांधी का पदनाम एक *अवैतनिक* नेत्र शल्यचिकित्सक है।

34.3. वेतन के विपरीत 4000 रुपये प्रति माह मानदेय घोषित किया गया है।

34.4. प्रति माह 4000 रुपये के अलावा, डॉ. गांधी को ओपीडी से प्रत्यर्थी 3 की कमाई का एक प्रतिशत, अस्पताल

---

<sup>40</sup> (1986) 1 एससीसी 32 : 1986 एससीसी (एल एंड एस) 155

<sup>41</sup> (2001) 3 एससीसी 36 : 2001 एससीसी (एल एंड एस) 504

में भर्ती बिलों का ऑपरेशन शुल्क घटक और कक्ष विज़िटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है।

34.5. मध्यस्थता खंड जो इस संविदा के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों की बात करता है, उसे संस्थान की प्रबंध समिति को भेजा जाएगा, प्रबंध समिति का निर्णय अंतिम होगा, और यह भी एक ऐसा खंड है जो शुद्ध स्वामी-सेवक संबंध में असामान्य है।

34.6. तथ्य यह है कि नियुक्ति संविदात्मक है - जो 3 साल के लिए - और केवल आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है, इस तथ्य का एक और संकेतक है कि संविदा सेवा के लिए है, जो कार्यकाल आधारित है।

34.7. यह तथ्य कि संविदा की समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस द्वारा हो सकती है, फिर से दिखाएगा कि पक्षकारगण एक-दूसरे के साथ स्वामी-सेवक की तुलना में समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं।

34.8. अनुबंध का खंड XI यह भी स्पष्ट करता है कि डॉ. गांधी की जो पिछली नियुक्ति की गई थी वह इस संविदा के अस्तित्व में आते ही समाप्त हो जाएगी, डॉ. गांधी अब संस्थान के नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रहेंगे।

35. उपरोक्त कारकों के विपरीत, जो संविदा को सेवा के लिए संविदा होने की ओर इशारा करते हैं, निम्नलिखित कारक विपरीत दिशा की ओर इशारा करेंगे:

35.1. रोज़गार पूर्णकालिक है। डॉ. गांधी कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं, और खंड IV के तहत डॉ. गांधी को किए जाने वाले सात प्रकार के कार्यों के अलावा, समय के दौरान बनने वाला कोई अन्य कार्य भी नियोक्ता के विवेक पर उन्हें दिया जा सकता है।

35.2. डॉ. गांधी को नियोक्ता द्वारा दिए गए साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन काम करना होगा। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि समय-समय पर प्रचलित संस्थान के अवकाश नियमों द्वारा शासित होने के बावजूद, डॉ. गांधी किसी भी प्रकार के किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे जो कि खंड V के तहत संस्थान के अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू हो सकता है।

35.3. डॉ. गांधी समय-समय पर लागू होने वाले और संस्थान के नियमित कर्मचारियों पर लागू होने वाले संस्थान के आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे।

35.4. अनुशासनहीनता या विश्वास के उल्लंघन के सिद्ध मामले की स्थिति में, संस्थान के पास कोई भी मुआवज़ा दिए बिना किसी भी समय संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।



36. यदि उपरोक्त कारकों को तराजू पर तौला जाए, तो यह स्पष्ट है कि जो कारक सेवा के लिए संविदा को एक बनाते हैं, वे उन कारकों पर भारी पड़ते हैं जो इसकी विपरीत दिशा की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पक्षकारगण के उद्देश्य को संविदा की शर्तों से देखा जाना है। संविदा की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि संविदा सेवा के लिए है, और संविदा शुरू होने की तिथि से, डॉ. गांधी अब संस्थान के नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रहेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी सेवाएँ अब नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र पेशेवर के रूप में हैं। दूसरे, पारिश्रमिक को मानदेय के रूप में वर्णित किया गया है, और इस स्थिति के अनुरूप कि डॉ. गांधी अपने आप में संस्थान में काम करने वाला एक स्वतंत्र पेशेवर है, उन्हें लाभ का एक हिस्सा मिलता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। तीसरा, वह समान शर्तों पर अनुबंध करता है क्योंकि अनुबंध तीन साल के लिए होता है, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है। चौथा, उसकी सेवाएँ संस्थान के अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह सामान्य तरीके से समाप्त नहीं की जा सकतीं, बल्कि दोनों तरफ़ से नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं। तथ्य यह है कि डॉ. गांधी संस्थान पर अपना पूरा ध्यान देंगे, यह दिहाड़ी तौर पर किए गए काम का विपरीत पक्ष है, जो कि, जैसा कि ऊपर दिए गए कुछ निर्णयों में माना गया है, फिर भी एक तटस्थ कारक होने

के कारण, सेवा की संविदा के बराबर हो सकता है। इसी तरह, यह तथ्य कि डॉ. गांधी को अपना पूरा ध्यान संस्थान पर लगाना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अन्य सभी कारकों को छोड़कर संविदा सेवा में से एक है। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह बताना आवश्यक है कि डॉ. गांधी संस्थान के आचरण नियमों और अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे, लेकिन किसी अन्य नियम से नहीं। और भले ही छुट्टी के नियम डॉ. गांधी पर लागू होते हैं, क्योंकि वह एक नियमित कर्मचारी नहीं हैं, वह किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं है जैसा कि अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू हो सकता है। समान रूप से, डॉ. गांधी और संस्थान के बीच विवादों की मध्यस्थता को संस्थान की प्रबंध समिति को भेजे जाने से यह पता चलेगा कि उन्होंने मालिक और नौकर के रूप में नहीं बल्कि नियोक्ता और स्वतंत्र पेशेवर के रूप में संविदा में प्रवेश किया है। उपरोक्त सभी का एक परिप्रेक्ष्य निश्चित रूप से आर्थिक वास्तविकता परीक्षण को लागू करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि पक्षकारगण के बीच हुआ संविदा एक संस्थान और एक स्वतंत्र पेशेवर के बीच है।"

(ज़ोर दिया गया)

**61.10** प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17 के परंतुक के खंड (ग) में "सेवा की संविदा" अभिव्यक्ति का उपयोग, विशेष रूप से कंपनी में "प्रशिक्षुता" शब्द का

उपयोग यह स्पष्ट करता है कि यह खंड समान लोगों के बीच संविदा के मामलों पर लागू नहीं होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सेवा प्रदान करने के लिए संपर्क करता है जैसे कि, वर्तमान मामले में, किसी फ़िल्म के लिए पटकथा लिखना और निर्देशन करना। उच्चतम स्तर पर, ऐसा संविदा केवल सेवा के लिए संविदा होगा न कि सेवा की संविदा।

61.11 धारा 17 का खंड (घ) स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

61.12 *निस्संदेह, निष्कर्ष यह है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17, सत्यजीत रे, फिल्म नायक की पटकथा के लेखक के रूप में, उक्त फिल्म में प्रतिलिप्यधिकार के पहले मालिक थे।*

61.13 *श्री दासवानी का यह तर्क कि वादी फिल्म नायक की पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार का मालिक है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है।*

62. प्रतिवादी के पास कौन से अधिकार हैं?

62.1 प्रतिलिप्यधिकार के मालिक में निहित अधिकारों को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14 में शामिल किया गया है, जो "प्रतिलिप्यधिकार" का अर्थ बताती है। धारा 14(1) में खंड (क) के अनुसार, "प्रतिलिप्यधिकार", किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कार्य के मामले में, (i) किसी भी भौतिक रूप में

कार्य के पुनरुत्पादन और (ii) कार्य के अनुकूलन को अधिकृत करता है। धारा

2(क) में "अनुकूलन" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है,

(i) किसी साहित्यिक कार्य या कलात्मक कार्य के संबंध में, सार्वजनिक रूप से या अन्यथा प्रदर्शन के माध्यम से शब्द का नाटकीय कार्य में रूपांतरण [उप-खंड (ii) के माध्यम से] और

(ii) किसी साहित्यिक कार्य या नाटकीय कार्य के संबंध में, कार्य का कोई संक्षिप्तीकरण या कार्य का कोई भी संस्करण जिसमें कहानी या क्रिया को पूरी तरह या मुख्य रूप से चित्रों के माध्यम से किसी पुस्तक में या किसी पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका या इसी तरह की पत्रिका में पुनरुत्पादन के लिए उपयुक्त रूप में व्यक्त किया जाता है [उपखंड (iii) के तहत]।

चूँकि पटकथा के उपन्यासीकरण में पटकथा का संक्षिप्तीकरण शामिल नहीं है, या इसे एक ऐसे संस्करण में परिवर्तित करना शामिल नहीं है जिसमें कहानी या कार्रवाई को पूरी तरह से या मुख्य रूप से किसी पुस्तक में पुनरुत्पादन के लिए उपयुक्त चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए उपन्यासीकरण धारा 2(क) में परिभाषित अनुसार "अनुकूलन" नहीं है।

62.2 हालाँकि, उपन्यासीकरण में निश्चित रूप से पटकथा का भौतिक रूप में पुनरुत्पादन शामिल होगा। *फ्रांसिस डे एंड हंटर लिमिटेड बनाम ब्रॉन*<sup>42</sup> मामले में

---

<sup>42</sup> (1963) 2 ऑल ईआर 16 (सीए)

अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "पुनरुत्पादन" को समान पुनरुत्पादन होने की आवश्यकता नहीं है; यह पर्याप्त है यदि कथित अतिलंघनकारी कार्य काफ़ी हद तक मूल कार्य के समान है"। इसी तरह के शब्दों में, **बी.सी.एस. ब्यूरो बनाम यूनाइटेड कंसर्न**<sup>43</sup> मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने पुनरुत्पादन को "अंततः किसी चीज़ की आवश्यक विशेषताओं के लिए या किसी माध्यम से प्रतिनिधित्व" के रूप में परिभाषित किया। वाद में वादी का मामला यह है कि आक्षेपित उपन्यास सत्यजीत रे द्वारा लिखित पटकथा की एक शाब्दिक प्रति थी। ऐसा होने पर, उपन्यास स्पष्ट रूप से पटकथा का "भौतिक रूप में पुनरुत्पादन" है।

**62.3** इसलिए, फ़िल्म "नायक" की पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार के पहले मालिक के रूप में, पटकथा को उपन्यासीकृत करने का अधिकार भी सत्यजीत रे के पास था। वह अधिकार उसके द्वारा समनुदेशित किया जा सकता है - और, उसके निधन के बाद, उसके बेटे और अन्य लोगों द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समनुदेशित किया जा सकता है, जिनके पास प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 18(1)<sup>44</sup> के तहत अधिकार हस्तांतरित हुआ हो। इसलिए, प्रतिवादी के पक्ष में

<sup>43</sup> एआईआर 1967 मद्रास 381

<sup>44</sup> 18. प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन। -

(1) किसी विद्यमान कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या भावी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का होने वाला स्वामी, प्रतिलिप्यधिकार को या तो पूर्णतः या भागतः और या तो सामान्यतया या निर्वन्धनों के अध्यक्षीन और या तो प्रतिलिप्यधिकार की संपूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिए, किसी व्यक्ति को समनुदेशित कर सकेगा:

परंतु किसी भावी कृति के प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन की दशा में, समनुदेशन तभी प्रभावशील होगा जब कृति अस्तित्व में आ जाए:

परंतु यह और कि ऐसा कोई समनुदेशन तब तक ऐसी कृति के जो अस्तित्व में नहीं थी या उस समय, जब समनुदेशन किया गया था वाणिज्यिक उपयोग में नहीं थी समुपयोजन के किसी माध्यम या ढंग को लागू नहीं होगा

संदीप रे और एस.पी.एस.आर.ए. द्वारा फ़िल्म "नायक" की पटकथा को उपन्यासीकृत करने के अधिकार का समनुदेशन पूरी तरह से क्रम में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। दूसरी ओर, वादी द्वारा फ़िल्म "नायक" की पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार का प्राख्यान अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है और वास्तव में, यहाँ उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन है।

**62.4** इसलिए, सत्यजीत रे के निधन के बाद, फ़िल्म "नायक" की पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार उसके बेटे संदीप रे और एस.पी.एस.आर.ए. के पास चला गया। इसलिए, संदीप रे और एस.पी.एस.आर.ए. द्वारा प्रतिवादी को पटकथा को उपन्यासीकृत करने का अधिकार प्रदान करना पूरी तरह से उचित है। मैं यहाँ उल्लेख करूँगा कि वादी ने प्रतिवादी को फ़िल्म की पटकथा को उपन्यासीकृत करने के अधिकार के अनुदान को इस तर्क के अतिरिक्त किसी भी आधार पर खारिज करने का विकल्प नहीं चुना है कि पटकथा में प्रतिलिप्यधिकार, न तो संदीप रे और एस.पी.एस.आर.ए., लेकिन वादी के पास है। वह विवाद, जैसा कि मैंने पहले ही पाया है, पूरी तरह से निराधार है।

---

जब तक कि ऐसे समनुदेशन में कृति के समुपयोजन के ऐसे माध्यम या ढंग के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से निर्देश न किया गया हो:

परंतु यह भी कि किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति का रचयिता, रचयिताओं के विधिक वारिसों या संग्रहण और वितरण संबंधी किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सिवाय किसी सिनेमा हाल में चलचित्र फिल्म के साथ सार्वजनिक रूप से कृति को संसूचित करने से भिन्न किसी रूप में ऐसी कृति के उपयोग के लिए प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ समान आधार पर बांटे जाने वाले स्वामिस्वों को प्राप्त करने के अधिकार का समनुदेशन या अधित्यजन नहीं करेगा और इसके तत्प्रतिकूल कोई करार शून्य होगा:

परंतु यह भी कि किसी ऐसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति का जिसे ध्वन्यंकन में सम्मिलित किया गया हो किन्तु वह किसी चलचित्र फिल्म का भागरूप न हो, रचयिता, रचयिताओं के विधिक वारिसों या संग्रहण और वितरण संबंधी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सिवाय ऐसी कृति के किसी उपयोग के लिए प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ समान आधार पर बांटे जाने वाले स्वामिस्वों को प्राप्त करने के अधिकार का समनुदेशन या अधित्यजन नहीं करेगा और इसके प्रतिकूल कोई समनुदेशन शून्य होगा।

### अन्य अभिवचन

63. श्री दासवानी द्वारा इस तथ्य पर बहुत ज़ोर दिया गया कि फ़िल्म "नायक" के संबंध में सभी खर्च वादी द्वारा वहन किए गए थे। याचिका वादी की सहायता नहीं कर सकती। भारत में प्रतिलिप्यधिकार एक कानून व्यवस्था है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं हो सकता। श्री दासवानी का यह अभिवचन कि फ़िल्म के निर्माण और उसके व्यावसायिक दोहन पर सारा धन उनके कक्षीकार द्वारा खर्च किया गया था, इसलिए उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

64. श्री दासवानी ने वादी और प्रतिवादी के बीच पत्रों पर भी भरोसा करने की माँग की, जिसमें उनके अनुसार, प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि फ़िल्म की पटकथा का प्रतिलिप्यधिकार उसके कक्षीकार के पास है। यह, फिर से, एक ऐसा अभिवचन है जो कहीं नहीं ले जाता है, क्योंकि प्रतिलिप्यधिकार सहमति से प्रदान नहीं किया जा सकता है, कानून के अनुसार नहीं। प्रतिलिप्यधिकार या तो उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम इसे प्रदान करता है, या उसके समनुदेशिती के पास, जिसे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इसे समनुदेशित किया गया है। इसके अलावा, मैं पक्षों के बीच के पत्रों में, प्रतिवादी द्वारा, फ़िल्म की पटकथा में वादी के प्रतिलिप्यधिकार की कोई

स्पष्ट स्वीकृति नहीं पा सका। इसलिए, तथ्यों के आधार पर भी, श्री दासवानी की प्रस्तुति आश्वस्त करने में विफल रहती है।

65. **रमेश सिप्पी** के निर्णय पर, जिस पर श्री दासवानी भरोसा करते हैं, केवल निर्माता को सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म का "लेखक" माना गया और परिणामस्वरूप, उसे प्रतिलिप्यधिकार का पहला मालिक माना गया। प्रस्ताव में कोई कमी नहीं हो सकती; हालाँकि, हमारा संबंध फ़िल्म की *पटकथा* के प्रतिलिप्यधिकार धारक से है।

66. यह तथ्य कि फ़िल्म एक दृश्य दर दृश्य, पंक्ति दर पंक्ति, पटकथा का लिप्यंतरण है, लेकिन स्पष्ट है, क्योंकि पटकथा का मतलब भी यही है। हालाँकि, यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों से उभरने वाली कानूनी स्थिति से अलग नहीं हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से एक सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म में प्रतिलिप्यधिकार की परिकल्पना करता है जो किसी भी साहित्यिक कार्य में प्रतिलिप्यधिकार से अलग और भिन्न होता है, भले ही साहित्यिक कार्य फ़िल्म का एक हिस्सा या संपूर्ण बन गया हो। धारा 13(4) पूर्व प्रतिलिप्यधिकार को बाद वाले को हटाने से रोकती है।

67. श्री दासवानी ने **आर.जी. आनंद** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विशेष भरोसा जताया। निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे सामने मौजूद मामले में इसका कोई औचित्य क्यों नहीं है। उसमें, एक नाटककार, जिसने एक नाटक लिखा था, ने एक सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के निर्माता पर मुकदमा करने की



माँग की, क्योंकि उसने बिना किसी अनुज्ञप्ति के नाटक पर आधारित फ़िल्म बनाई थी। श्री दासवानी ने प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हुआ है या नहीं यह जानने के लिए निम्नलिखित परीक्षण पर ज़ोर दिया, जो उक्त निर्णय के पैरा 46 में बताया गया है:

“3. प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित परीक्षणों में से एक यह देखना है कि क्या दोनों कृतियों को पढ़ने या देखने के बाद पाठक, दर्शक या देखने वाले की स्पष्ट राय बन जाती है और उसे यह स्पष्ट आभास हो जाता है कि बाद वाली कृति मूल की प्रतिलिपि प्रतीत होती है।”

जिस अवलोकन पर भरोसा किया गया है वह पूरी तरह से संदर्भ से परे है। अपने प्रस्तुतीकरण को आगे बढ़ाते हुए, श्री दासवानी ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि *आर.जी. आनंद* का निर्णय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 की धारा 1(2)(घ) के साथ सहपठित धारा 2(1) के संदर्भ में किया गया था, जिसके तहत विवाद उत्पन्न हुआ था। धारा 2(1) में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना गया है "किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो प्रतिलिप्यधिकार के मालिक की सहमति के बिना, ऐसा कुछ भी करता है जिसे करने का एकमात्र अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के मालिक को दिया गया है", और धारा 1(2)(घ) में प्रतिलिप्यधिकार से उत्पन्न अधिकारों में, "किसी भी साहित्यिक, नाटकीय या

संगीतमय कार्य के मामले में, कोई भी सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म बनाने का अधिकार" शामिल है। इस प्रकार, साहित्यिक कृति के लेखक से अनुज्ञप्ति लिए बिना किसी व्यक्ति द्वारा किसी साहित्यिक या नाटकीय कृति की सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म का निर्माण प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाता है। वर्तमान मामले में, पटकथा के लेखक की अनुमति के बिना फ़िल्म 'नायक' की पटकथा से किसी भी सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के निर्माण से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारे समक्ष जो मामला है, उसमें फ़िल्म 'नायक' की पटकथा में सही प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा, पटकथा को उपन्यासीकृत करने का अधिकार का एक वैध समनुदेशन शामिल है, जो "किसी भी भौतिक रूप में कार्य का पुनरुत्पादन" होगा। इसलिए, **आर.जी. आनंद** श्री दासवानी की सहायता नहीं कर सकते।

68. **आई.पी.आर.एस.** भी श्री दासवानी की सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार उस मामले में संविवाद के मुद्दे को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के शुरुआती पैराग्राफ़ में पकड़ लिया है:

“क्या प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के मद्देनज़र, संगीतकार, गीतकार का मौजूदा और भविष्य का अधिकार समनुदेशन के लिए सक्षम है और क्या सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म का निर्माता उसी व्यक्ति को शामिल करके उसे हरा सकता है।”

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट का पैरा 8 "निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु" की पहचान करता है कि "क्या गीत या संगीत कृति के संगीतकार [जिसका अर्थ अधिनियम की धारा 2(त) के संदर्भ में केवल एक उल्लेखनीय रूप से लिखित, मुद्रित या ग्राफ़िक रूप से निर्मित या पुनरुत्पादित संगीत है] के पास गीत या संगीत कृति पर प्रतिलिप्यधिकार है यदि वह किसी सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के साउंड ट्रैक में इसके समावेश के लिए किसी सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के लेखक (मालिक) को अनुज्ञप्ति या अनुमति देता है"।

69. इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2(च) में, परिभाषा के अनुसार, अभिव्यक्ति "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म", "साउंड ट्रैक, यदि कोई हो" शामिल है। इसके विपरीत, फिल्म की पटकथा किसी भी तरह से "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म" की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसके बाद, रिपोर्ट का पैरा 15 निम्नानुसार निरीक्षण और धारण करने के लिए आगे बढ़ता है:

“15. ऊपर प्रस्तुत धारा 2 का व्याख्या खंड (च), जो संपूर्ण नहीं है, धारा 14(1)(ग)(iii) की निरंतरता में पढ़ने पर संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि शब्द "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म" में फिल्म से जुड़ा एक साउंड ट्रैक शामिल है। इन प्रावधानों के आलोक में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि एक "सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म" को साउंड ट्रैक में सन्निहित ध्वनियों को शामिल करने के

लिए लिया जाना चाहिए जो फ़िल्म से जुड़ी हैं। धारा 13 "सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म" को "कार्य" के एक विशिष्ट और अलग वर्ग के रूप में मान्यता देती है और घोषणा करती है कि प्रतिलिप्यधिकार पूरे भारत में मौजूद रहेगा। धारा 14 जो धारा 13 में उल्लिखित कार्यों के विभिन्न वर्गों में मौजूद अधिकारों की गणना करती है, यह प्रावधान करती है कि किसी साहित्यिक या संगीतमय कार्य के मामले में प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ है अन्य बातों के साथ-साथ (क) सार्वजनिक रूप से कार्य करने या प्रदर्शन कराने का अधिकार और (ख) कार्य के संबंध में सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म या रिकॉर्ड बनाने या बनाने के लिए अधिकृत करना। इसमें यह भी प्रावधान है कि सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के मामले में प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ अन्य अधिकारों के अलावा, सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने या आयोजित करने का अधिकार है, अर्थात् फ़िल्म को तब तक प्रदर्शित करने का अधिकार, जब तक इसमें सार्वजनिक रूप से देखने के लिए दृश्य छवियाँ शामिल हों और जहाँ तक इसमें सार्वजनिक रूप से सुनी जाने वाली ध्वनियाँ शामिल हों। धारा 13(4) जिस पर श्री अशोक सेन ने अपने तर्कों के समर्थन में बहुत अधिक भरोसा किया है, यह बताता है कि सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म या अभिलेख में प्रतिलिप्यधिकार किसी भी काम में अलग प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिसके संबंध में या उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से, फ़िल्म, या जैसा भी मामला हो, अभिलेख बनाया गया है। हालाँकि पहली नज़र में एक ओर धारा 13(4) और धारा 14(1)(ए)(iii) और दूसरी ओर धारा 14(1)(ग)(ii) के बीच विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, लेकिन उक्त प्रावधानों की सूक्ष्म समीक्षा करने और यांत्रिक निर्माण के बजाय

सामंजस्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि एक बार किसी गीत या संगीत रचना के लेखक अपने प्रतिलिप्यधिकार के एक हिस्से के साथ एक फ़िल्म निर्माता को उसके काम के संबंध में एक सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है और इस तरह उसके काम को एक सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के साउंड ट्रैक पर शामिल या रिकॉर्ड किया जाता है, बाद वाला सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के पूरा होने पर अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के आधार पर एक प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करता है जो उसे अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से काम करने का विशेष अधिकार देता है अर्थात् फ़िल्म को तब तक सार्वजनिक करने का कारण बनता है जब तक इसमें दृश्य छवियाँ शामिल होती हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है और जहाँ तक इसमें ध्वनिक भाग शामिल होता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन के लिए गीत या संगीत कार्य के लेखक (संगीतकार) की किसी भी अतिरिक्त अनुमति के बिना सार्वजनिक रूप से सुना जाने वाला गीत या संगीत कार्य शामिल है। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त परिस्थितियों में समग्र रूप से सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म में एक अलग प्रतिलिप्यधिकार निहित हो जाता है, जो 1951 में स्थापित ब्रिटिश प्रतिलिप्यधिकार समिति के शब्दों में फ़िल्म की नकल करने और सार्वजनिक रूप से इसके प्रदर्शन दोनों से संबंधित है। इस प्रकार यदि किसी गीत या संगीत कृति का लेखक (संगीतकार) किसी सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म निर्माता को सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के साउंड ट्रैक पर रिकॉर्ड करके अपनी रचना की सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म बनाने के लिए अधिकृत करता है, तो वह अपने प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन की शिकायत नहीं

कर सकता है यदि सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म का लेखक (मालिक) फ़िल्म के साउंड ट्रैक पर रिकॉर्ड किए गए गीत या संगीत कार्य को सार्वजनिक रूप से सुनने का कारण बनता है और अधिनियम की धारा 13 (4) में कुछ भी, जिस पर श्री अशोक सेन ने दृढ़ता से भरोसा किया है, वह अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के आधार पर फ़िल्म के लेखक (मालिक) द्वारा अर्जित अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, किसी गीत या संगीत कृति के संगीतकार को सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के एक भाग के अलावा लाभ के लिए इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का अधिकार रहता है और उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक गीत या संगीत कार्य का लेखक (संगीतकार) जिसने एक सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म निर्माता को अपने कार्य की एक सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म बनाने के लिए अधिकृत किया है और इस तरह उसे सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के साउंड ट्रैक पर शामिल या रिकॉर्ड करके अपने काम को उपयुक्त बनाने की अनुमति दी है, तो वह फ़िल्म के लेखक (मालिक) को फ़िल्म के ध्वनिक हिस्से को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन या प्रक्षेपित या प्रदर्शित करने से रोक नहीं सकता है रेडियो-प्रसार द्वारा फ़िल्म के संचार को संप्रेषित करने या अधिकृत करने के ऐसे साउंडट्रैक का उपयोग करके फ़िल्म से जुड़े साउंड ट्रैक के किसी भी हिस्से में रिकॉर्डिंग को मूर्त रूप देने से लाभ कमाने या कोई रिकॉर्ड बनाने से, क्योंकि अधिनियम की धारा 14 (1) (ग) स्पष्ट रूप से सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के प्रतिलिप्यधिकार के मालिक को ये सभी काम करने की अनुमति देती है। ऐसे मामलों में, सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के लेखक (मालिक) के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने गीत या संगीत कृति के

संगीतकार की किसी भी चीज़ को गलत तरीके से अधिग्रहित कर लिया है। कोई भी अन्य निर्माण न केवल अधिनियम की धारा 2 के खंड (च), (ड), (म), धारा 13(1)(ख) और धारा 14(1)(ग) के व्यक्त प्रावधानों को समाप्त कर देगा बल्कि यह विधायिका के इरादे को भी विफल कर देगा, जिसने अभिव्यक्ति के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में सिनेमैटोग्राफ़ फ़िल्म के बढ़ते महत्व और इसके उत्पादन में शामिल अत्यधिक जटिल तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रिया और भारी पूँजी परिव्यय को देखते हुए, इसे एक अलग इकाई के रूप में मान्यता देने और फ़िल्म से जुड़े साउंड ट्रैक के किसी भी हिस्से में रिकॉर्डिंग को शामिल करने वाले रिकॉर्ड को ऐसे साउंड ट्रैक का उपयोग करके सामान्य रूप से समझे जाने वाले रिकॉर्ड से अलग मानने की माँग की है।

इसलिए, *आई.पी.आर.एस.* का मुद्दा मेरे समक्ष मौजूद मुद्दे से किसी भी तरह से समानता नहीं रखता है। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या, संविदा द्वारा, किसी फ़िल्म के निर्माता को, उसके द्वारा बनाए गए संगीत कार्य को एक फ़िल्म में शामिल करने की अनुमति देने पर, ऐसे संगीत कार्य का लेखक फ़िल्म, जिसमें उनकी रचना शामिल थी, के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोक सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया। फिर भी, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संगीत कृति के निर्माता का कृति का अन्यथा वाणिज्यिक दोहन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

70. **आई.पी.आर.एस.** का पैरा 17, जिस पर श्री दासवानी ने विशेष निर्भरता रखी थी, इस प्रकार है:

“17. यह हमें प्रश्न के मूल में ले जाता है, अर्थात्, क्या सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म का निर्माता संगीतकार या गीतकार को शामिल करके उसके संगीत के अधिकार को हरा सकता है। इस प्रश्न के समाधान की कुंजी ऊपर दिए गए अधिनियम की धारा 17 के परंतुकों (ख) और (ग) में निहित है जो मामले को संदेह से परे रखती है। इनमें से प्रथम परंतुकों अर्थात् परंतुक (ख) के अनुसार जब एक सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म निर्माता अपनी सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म बनाने, या संगीत या गीत की रचना करने के उद्देश्य से पुरस्कार या मूल्यवान विचार के लिए संगीत के संगीतकार या गीतकार को नियुक्त करता है, अर्थात्, फिल्म से जुड़े साउंड ट्रैक में समावेश या अवशोषण के लिए ध्वनियाँ, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, एक सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म में शामिल हैं, वह उसमें प्रतिलिप्यधिकार का पहला मालिक बन जाता है और इस प्रकार रचित गीत या संगीत के संगीतकार का कोई प्रतिलिप्यधिकार तब तक अस्तित्व में नहीं रहता जब तक कि एक ओर गीत या संगीत के संगीतकार और दूसरी ओर सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के निर्माता के बीच कोई विपरीत अनुबंध न हो। उपरोक्त परंतुक (ग) के अनुसार वही परिणाम आता है यदि संगीत या गीत के संगीतकार को काम की रचना करने के लिए सेवा या शिक्षता की संविदा के तहत नियोजित किया जाता है। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी संगीतकार या गीतकार के अधिकारों को



सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के निर्माता द्वारा अधिनियम की धारा 17 के परंतुक (ख) और (ग) में निर्धारित तरीके से पराजित किया जा सकता है।"

धारा 17 का परंतुक (ख), अपने स्पष्ट शब्दों में, जहाँ तक सिनेमैटोग्राफ़ फिल्मों का संबंध है, *किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर मूल्यवान विचार के लिए सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म के निर्माण को संदर्भित करता है। उच्चतम न्यायावय का निर्णय कि, यदि एक सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म का निर्माता किसी फिल्म के लिए एक संगीत निर्देशक या गीतकार को साउंडट्रैक की रचना करने के लिए नियुक्त करता है, तो परंतुक (ख) संगीत निर्देशक या गीतकार को उसके या उसके प्रतिलिप्यधिकार को संगीत या गीत में विभाजित करने का काम करेगा, जो तब फिल्म के निर्माता के साथ निहित होगा, जैसा कि धारा 14 (1) (ग) (iii) की पृष्ठभूमि में रिपोर्ट के पैरा 15 से स्पष्ट है, जो सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म में प्रतिलिप्यधिकार धारक अर्थात् निर्माता को इस तरह के साउंडट्रैक का उपयोग करके फिल्म से जुड़े साउंड ट्रैक के किसी भी हिस्से में रिकॉर्डिंग को मूर्त रूप देने का अधिकार प्रदान करता है। फ़िल्म की पटकथा के अनुसार निर्माता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।*

71. *आई.पी.आर.एस.*, इसलिए, एक पूरी तरह से अलग, और भिन्न, धुरी पर बदल जाता है, और श्री दासवानी की मदद नहीं कर सकता है। किसी को केवल

उस अतिशयोक्ति की याद आती है, जो अब तक घिसी-पिटी है, कि किसी निर्णय को मिसाल के तौर पर लागू करने से पहले, उस तथ्यात्मक और विधिक मैट्रिक्स को ध्यान में रखना होगा जिसमें निर्णय दिया गया था।

72. कई अन्य निर्णयों को उद्धृत किया गया था, और उनका उल्लेख इस निर्णय के मुख्य भाग में किया गया है। हालाँकि, मैं उनमें से प्रत्येक का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि जिन प्रस्तावों के लिए श्री दासवानी ने उक्त निर्णयों पर भरोसा किया था, उनका उत्तर यहाँ ऊपर दी गई टिप्पणियों और निष्कर्षों से दिया गया है, जो कानून के स्पष्ट शब्दों पर आधारित हैं। केवल यह बताना पर्याप्त है कि मुझे बाध्यकारी पूर्ववर्ती मूल्य का कोई निर्णय नहीं मिला है, जिसके साथ मेरे निष्कर्ष अनुरूप नहीं हैं।

## **निष्कर्ष**

73. उपरोक्त चर्चा के लिए, वादी को विधि की दृष्टि में, प्रतिवादी को फ़िल्म "नायक" की पटकथा का उपन्यासीकरण करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

74. तदनुसार, वादपत्र के पैरा 34 में प्रार्थना (क) मंजूर नहीं की जा सकती। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

75. अंतर.आ. 9516/2021 को, जिस पर केवल वादपत्र के पैरा 34 में प्रार्थना (क) के संबंध में जोर दिया गया है, तदनुसार, अनुमति दी जाती है।

न्या., सी. हरि शंकर

23 मई 2023

आर.बी.

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

*अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*